छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ की गृह पत्रिका

# संकल्प

दिसम्बर 2025 | वर्ष 22 | अंक 05-06

# ऊर्जावान छत्तीसगढ़

## २५ बरस की गर्वित विरासत, आरंभ नये युग का







सी एस पी जी सी एल CSPGCL

CSPTCL

CSPDCL

छत्तीसगढ़ की धरती पर 37,580 मेगावॉट बिजली उत्पादन की तैयारी...
नई सोच - नए प्रयास से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी सहित
विभिन्न केन्द्रीय-राज्य स्तरीय उपक्रमों, निजी संस्थाओं तथा
व्यक्तिगत सौर ऊर्जा उत्पादकों द्वारा भविष्य में उत्पादित की जाने वाली क्षमता

# 37580 मेगावॉट

(वर्तमान स्थापित क्षमता 30,510 मेगावॉट के अतिरिक्त) :-



- **न्यूक्लियर** (पीएसयू) - 4200 मेगावॉट
- **ताप विद्युत** (निजी) - 8380 मेगावॉट
- **ताप विद्युत** (पीएसयू) - 3720 मेगावॉट
- **पंप स्टोरेज** (पीएसयू) - 7300 मेगावॉट
- **पंप स्टोरेज** (निजी) - 5000 मेगावॉट
- **सौर ऊर्जा** -
  - पीएम कुसुम - 3975 मेगावॉट
  - प्रधानमंत्री सूर्यघर - 1800 मेगावॉट
  - अन्य रूफटॉप सोलर - 1000 मेगावॉट
  - ओपन एक्सेस - 1200 मेगावॉट
  - फ्लोटिंग सोलर - 630 मेगावॉट
  - शासकीय भवन - 375 मेगावॉट



# संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल व इसकी उत्तरवर्ती पॉवर कंपनियों की रजत जयंती के अवसर पर उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तीनों पॉवर कंपनियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि स्टेट पॉवर कंपनीज़ की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की उपलब्धियों को सहेजने के लिए संकल्प के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश ने इन 25 वर्षों में विकास के अनेक शिखरों को स्पर्श किया है और इसमें पॉवर कंपनियों, अधिकारियों-कर्मचारियों और विद्युत विकास में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का समर्पित योगदान रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2047 के विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी विकास के उच्च लक्ष्य निर्धारित किये हैं। माननीय मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा भी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

यह अवसर 25 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों का उत्सव मनाने का तो है ही, साथ ही नये लक्ष्यों के लिए अपने संकल्पों को सुदृढ़ करने का भी है मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी संपूर्ण प्रतिभा, लगन, परिश्रम और समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने के लिए अपना योगदान दें। यह प्रकाशन स्मृति ग्रंथ के साथ ही प्रेरणा का पुंज भी बने, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

**(विष्णु देव साय)**
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़














विद्युत विकास के लिए नयी ऊर्जा का संचार करते हुए श्री सुबोध कुमार सिंह

# संदेश



मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विगत 25 वर्षों के प्रयासों और उपलब्धियों पर केन्द्रित गृह पत्रिका संकल्प के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह सुखद संयोग है कि राज्य गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल तथा उत्तरवर्ती स्टेट पॉवर कंपनीज़ का भी यह रजत जयंती वर्ष है। निश्चित तौर पर यह 25 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के अभूतपूर्व विकास के रहे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अत्यंत संतोष का विषय है कि रजत जयंती वर्ष में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों के लिए विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तैयार कर, उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। इन परियोजनाओं में रणनीतिक भागीदारी और समुचित पूंजी निवेश हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी पॉवर कंपनियों द्वारा जिस कुशलता से विगत 25 वर्षों का गौरवशाली सफर तय किया है, उसमें विस्तार करते हुए भावी लक्ष्य भी श्रेष्ठतम तरीकों से प्राप्त किये जायेंगे।

प्रकाशन अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं !

**(सुबोध कुमार सिंह)**
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
एवं अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी

# संदेश



अत्यंत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ का रजत जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं उत्पादन, पारेषण तथा वितरण तीनों कंपनी के सेवारत, सेवानिवृत्त साथियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आप सबका सराहनीय योगदान भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व, इसकी कार्यप्रणाली, प्रदेश में विद्युत विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा देश के पॉवर सेक्टर में उच्च स्थान पर है। बिजली कंपनियों के कार्य-निष्पादन के निर्धारित पैमानों में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी विशेष प्रतिष्ठा कायम की है। उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक के लिए जो नये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, वे अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। इससे प्रदेश तथा देश के विकास को गति मिलेगी।

मेरी कामना है कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारीगण अपने को नई चुनौतियों के लिए तैयार रखें तथा सफलता के नये शिखरों को छूने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। संकल्प के इस विशेषांक की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित !

**(डॉ. रोहित यादव)**
सचिव, ऊर्जा एवं जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन
तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी



वृक्षारोपण महाभियान का आगाज करते हुए डॉ. रोहित यादव

# संदेश



छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात्, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये। राज्य सरकार की सकारात्मक तथा उदार नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की अगुवाई में स्टेट सेक्टर में नये बिजलीघरों की स्थापना का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ में छत्तीसगढ़, केन्द्रीय क्षेत्र तथा निजी विद्युत उत्पादकों और निवेशकों का गढ़ भी बन गया। इस दौरान राज्य के बिजलीघरों ने कार्य-निष्पादन के नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये। भारत के स्टेट सेक्टर के तमाम बिजलीघरों के कार्य-निष्पादन की तुलना में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृह विभिन्न मापदण्डों पर देश में अव्वल रहे।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, माननीय अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के मार्गदर्शन में हमने भविष्य की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए स्टेट सेक्टर के लिए बड़ी परियोजनाएं हाथ में ली हैं, साथ ही सेंट्रल सेक्टर तथा निजी क्षेत्र को भी राज्य में पूंजी निवेश के लिए तैयार किया है ताकि उसका लाभ भी राज्यांश के रूप में बड़े पैमाने पर मिल सके। छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ की रजत जयंती के अवसर पर यह कहना समीचीन होगा कि हम अब बहुत मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं और संकल्पबद्ध हैं कि प्रदेश और देश को विद्युत उपलब्ध कराने में भविष्य में भी हमारी बड़ी भूमिका होगी। संकल्प के विशेषांक की सफलता हेतु शुभकामनाओं सहित !

**(संजीव कुमार कटियार)**
प्रबंध निदेशक,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी

# संदेश



प्रदेश के माननीय उपभोक्ताओं को सतत व गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करना तीनों विद्युत कंपनियों जनरेशन, ट्रांसमिशन व वितरण का दायित्व है| छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की भूमिका जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। राज्य के विद्युत गृहों में उत्पादित बिजली एवं केन्द्रीय संस्थान जैसे एनटीपीसी व निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिजली को प्रदेश के हर क्षेत्र में पारेषण लाइनों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य पारेषण कंपनी की महती जिम्मेदारी होती है। इस हेतु पारेषण तंत्र का नियमित रूप से विद्युत मांग के अनुरूप सुदृढ़ीकरण करना व इसका समुचित रखरखाव करना अति आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि इन तमाम मापदण्डों पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी खरी उतरी है।

विगत 25 वर्षों में पारेषण प्रणाली के ट्रांसफार्मरों की क्षमता 3,552 एमवीए से बढ़कर 27,820 एमवीए हो जाना, पारेषण लाइनों की लंबाई 4,845 से बढ़कर 14,717 सर्किट किलोमीटर हो जाना, केन्द्रीय ग्रिड से पॉवर हस्तांतरण क्षमता पिछले 3 वर्षों में 2540 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में 4930 मेगावॉट हो जाना महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुबोध सिंह जी के निरंतर मार्गदर्शन में प्रदेश के माननीय उपभोक्ताओं के हित में पारेषण तंत्र में आवश्यक कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु कटिबद्ध हैं। प्रकाशन की सफलता के लिए शुभकामनाओं सहित !

**(राजेश कुमार शुक्ला)**
प्रबंध निदेशक,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी

# संदेश



राज्य निर्माण का 25 वाँ स्थापना वर्ष नए उत्साह और ऊर्जा का संदेश लेकर आया है। यह हमें इस बात का अवसर देता है कि हम बीते समय के उतार-चढ़ाव को निहारें, किए गए कार्यों का आकलन करें। हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि प्रगति के पथ पर निकले हम लोग बीते ढाई दशकों में कितना सफर तय कर पाए। विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य हमें शत-प्रतिशत विश्वास दिलाते हैं कि प्रयास की नीयत साफ और नियति आशानुरूप रही है। जिस नीयत से स्वतंत्र विद्युत मंडल बनाया गया उसे साबित करने में मंडल के हर एक अधिकारी और कर्मचारी ने जी जान लगाकर कार्य किया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पॉवर कंपनी के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिया है जिसके केन्द्र में राज्य के हर वर्ग का उपभोक्ता है जिसके लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत@2047 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो दृष्टि दी है उसे समय सीमा में साकार करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पॉवर कंपनी को दिया है। भविष्य को ध्यान में रखकर पॉवर कंपनी ने इस दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से कारगर कदम बढ़ा दिए हैं।

ढाई दशक पहले तक पिछड़ा कहलाने वाले इस प्रांत की पीड़ा को एक भूमिपुत्र होने के नाते मैंने भी महसूस किया है। राज्य गठन पूर्व छत्तीसगढ़ के साथ हुई उपेक्षा, उदासीनता और भेदभाव को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और लगातार बदलते समय के साथ नवीनता को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे वनाच्छादित क्षेत्रों समेत दुर्गम स्थानों पर निवासरत जनजातियों के घरों को रोशन करने में हम कामयाब हुए हैं। पूरे प्रदेश में बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति बनाए रखने का दायित्व मेरे लिए आत्मिक संतोष का विषय है। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़िया सही मायनों में सबले बढ़िया का उजियार प्रदेश ही नहीं देशभर में फैल रहा है।

प्रौद्योगिकी, नित नए सुधार और बदलाव के साथ हमारे जीवन को बदल रही है। ऐसे में हमारी भूमिका भी नवीनता को ग्राह्य करने वाली होनी चाहिए। यह बड़े ही आत्मसंतोष का विषय है कि हमने विद्युत उत्पादन, पारेषण के साथ वितरण क्षेत्र में हर उस बदलाव को स्वीकारा जो हमारी विद्युत सेवा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सके। स्मृतियों के पटल पर अंकित घटनाएं बताती हैं कि श्रम और साधना के बल पर जो तंत्र स्थापित हुआ वही आज विकास की तेज रफ्तार का प्रमुख आधार है। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी तक का यह सफर बहुत सी चुनौतियों, सुधारों और उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इन्हीं बातों को सार संग्रहित करने का प्रयास है संकल्प के विशेषांक का प्रकाशन।

आशा है कि संकल्प के विशेषांक के माध्यम से पॉवर कंपनी के हमारे साथी आत्म आकलन कर अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी, नई ऊर्जा के साथ विकासगामी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और विरासत में मिली उत्कृष्टता को सतत बनाए रखने में कामयाब होगी।

**(भीम सिंह कंवर)**
प्रबंध निदेशक,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी



वर्तमान संयुक्त प्रशासनिक मुख्यालय भवन, डंगनिया, रायपुर



प्रस्तावित संयुक्त प्रशासनिक मुख्यालय भवन, नवा रायपुर

# संदेश



हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी को छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को शुरूआत से लेकर 25 वर्षों का सफर तय करते हुए देखने का अवसर मिला है। जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का सफर किसी व्यक्ति की तरह ही राज्य तथा संस्थाओं के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।

छत्तीसगढ़ को राज्य गठन से जो नया अवसर मिला वह नई शताब्दी की नई अवधारणा, नये उत्साह और नये कौशल के साथ राज्य को गढ़ने का सुअवसर बना।

निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की मजबूत बुनियाद खड़ी करने में ऊर्जा की महती आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे अग्रजों ने की। राज्य विद्युत कंपनियों के प्रतिभावान अधिकारियों, समर्पित कर्मचारियों और ऊर्जा क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए तत्पर विभिन्न संस्थाओं और सहयोगियों का अतुलनीय योगदान इसमें दर्ज हुआ।

रजत जयंती के पावन अवसर पर हमे उन सभी महानुभावों का पावन स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने राज्य विद्युत कंपनियों को देश में उच्चतम मान-सम्मान-प्रतिष्ठा दिलाई है। हमारे प्रदेश के विद्युतकर्मियों ने विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण के साथ ही अन्या रचनात्मक क्षेत्रों में जो नाम कमाया है उसके कारण हमे मूल्यवान और कुशल मानव संसाधन तैयार करने वाले उत्कृष्ट संस्थान के रुप में भी जाना जाता है। रजत जयंती का यह गौरवशाली पड़ाव सुनहरे भविष्य का विश्वास जगाता है, इसे यादगार बनाने में यह प्रयास कारगर साबित होगा, ऐसी आशा है।

**(ए एम परियल)**
मुख्य अभियंता, मानव संसाधन
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी

# भावार्थ

प्यार सच्चा हो तो
राहें भी निकल आती हैं,
बिजलियां अर्श से खुद
रास्ता दिखलाती हैं.....

मशहूर शायर हसरत जयपुरी की यह गजल दरअसल यह बताती है कि जब हम अपनी माटी के लिए प्यार, श्रद्धा और समर्पण के साथ एक नए रास्ते पर चल निकलते हैं तो आसमानी आफत भी वरदान बन जाती है। तूफानी रात और घनघोर अंधेरे में चमकती हुई बिजली भी रास्तों को रोशन करती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के झंझावाती दौर को याद करें तो उन अंधेरों को याद करना जरूरी हो जाता है जो हमें विरासत में मिले थे। जाहिर है कि ये अंधेरे अविभाजित मध्यप्रदेश के हिस्से के रूप में मिले थे।

हमारा कोयला, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे मानव संसाधन, हमारा श्रम जिस बिजली का उत्पादन करते थे उसका बहुत कम हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिल पाता था। राज्य गठन के बाद सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदली और हमें अपना भाग्य विधाता बनने का अवसर मिला। यही से शुरू हुआ प्रदेश में रोशनी का सफर। हम बिजली के उत्पादक ही नहीं बल्कि उपभोक्ता भी बनने लगे। यह कहानी हर छत्तीसगढ़िया को बिजली की शक्ति से ऊर्जावान बनाने की कहानी है। रजत जयंती इस सफर का पड़ाव है। मंजिल तो सितारों के आगे है।

**(उमेश कुमार मिश्र)**
अति. महाप्रबंधक, जनसंपर्क
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियां

## संपादक



**उमेश कुमार मिश्र**
अति. महाप्रबंधक, जनसंपर्क

## संपादन सहयोग



**गोविन्द पटेल**
प्रबंधक



**अनामिका मंडावी**
प्रकाशन अधिकारी

## छाया



**संजय टेम्बे**
सहा. मुख्य छायाकार

**कार्यालय सहयोग**
सारिका साहू, प्रसन्न कुमार दुबे, शुभम बंछोर
फोन : 0771-2574702, 98936-24511
E-mail : procsphcl@gmail.com,
powercomu01@gmail.com

Scan QR to log in to Facebook

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए, कार्यालय अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) द्वारा प्रकाशित।


# अनुक्रम


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| पुरोधाओं के विचार | 8 |
| सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट | 12 |
| रजत जयंती वर्ष में एमओयू | 14 |
| चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सफरनामा | 16 |
| उत्पादन क्षमता का क्रमिक विकास | 17 |
| उत्पादन क्षमता तब और अब | 21 |
| लीक से हटकर कोयला खदान संचालन | 24 |
| पारेषण क्षमता विकास | 26 |
| स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, डंगनिया, रायपुर | 30 |
| स्वीकृत व प्रस्तावित अति उच्चदाब उपकेंद्र | 32 |
| वितरण तंत्र - उपभोक्ता सेवा का मंत्र | 38 |
| वितरण अधोसंरचना विकास एवं विस्तार | 41 |
| हितग्राहीमूलक योजनाएं | 44 |
| शहरों को अंडरग्राउंड केबलिंग की सौगात | 46 |
| बिजलीकर्मियों के बलिदान, शौर्य और समर्पण की गाथा... | 49 |
| प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना | 54 |
| उपभोक्ता-सेवाएं और सुविधाएं | 57 |
| नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन | 62 |
| पुरोधा : मण्डल से कंपनी तक | 65 |



छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। दो वर्षों बाद पुनः मुझे यह अवसर मिला। इस तरह मैंने दो कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। नवगठित राज्य में ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए जिससे राज्य एवं अन्य संस्थाओं को यहां बिजलीघर लगाने में सहूलियत हो। शासन की उदार नीतियों के कारण एक ओर जहां विद्युत उत्पादन बढ़ा वहीं दूसरी ओर विद्युत मण्डल की बेहतर कार्य संस्कृति के कारण अच्छे परिणाम मिले। विगत 25 वर्षों में मण्डल का स्वरूप बदला और इसने प्रदेश में विद्युत विकास के अनेक नये आयाम जोड़े। वर्तमान स्वरूप में स्टेट पॉवर कंपनीज़ जिस तरह सकारात्मक और उत्साहजनक तरीके से कार्य कर रही है, उससे भविष्य भी बेहतर दिखाई पड़ता है।

**▪ एस.के.मिश्रा**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल एवं पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के दौरान मैं न सिर्फ मण्डल के संस्थागत बदलाव का साक्षी बना बल्कि एक लंबे समय तक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी भी निभाई। आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि बदलाव से बेहतर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिली। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण जैसे हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे गए। प्रसन्नता का विषय है कि इस बीच ऊर्जा क्षेत्र के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो चुनौतियां आ रही थीं उनका सामना छत्तीसगढ़ के विद्युत कर्मियों ने बहुत कुशलता के साथ किया। नये राज्य के लिए आवश्यक विद्युत संरचना की स्थापना वास्तव में मील का पत्थर साबित हुई और इससे भविष्य के कई द्वार भी खुले।

**▪ पी. जाय उम्मेन**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल,छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियां एवं पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन



अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में अधोसंरचना विकास को लेकर एक संकुचित दृष्टिकोण दिखाई पड़ता था। अन्य क्षेत्रों के साथ ऊर्जा क्षेत्र को भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद राज्य अस्मिता और संसाधनों को लेकर शासन-प्रशासन के नजरिये में महत्वपूर्ण बदलाव आया। राज्य शासन की उदार नीतियों व संरक्षण के कारण राज्य के अलावा केंद्रीय उपक्रमों, निजी क्षेत्रों की पूंजी ऊर्जा क्षेत्र में आई। यही वजह है कि विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि के साथ ही पारेषण, वितरण व उपभोक्ता सेवा के नए आयाम स्थापित करने के सारे नए कीर्तिमान स्थापित हुए, जिनमें मेरी भी भूमिका रही। इस नींव पर अब छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ को लगातार आगे बढ़ने की शुभकामनाएं।

**▪ शिवराज सिंह**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ एवं पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भण्डार उपलब्ध था। अविभाजित राज्य के हिस्से के रूप में हमारे संसाधनों का वैल्यू एडिशन यहां नहीं हो पाता था। नया राज्य बनने से अपने संसाधनों के राज्य हित में बेहतर इस्तेमाल के रास्ते खुल गए। छत्तीसगढ़ के बिजली उत्पादन को देखते हुए राज्य में पारेषण और वितरण तंत्र का विकास तेजी से होने लगा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मण्डल तथा उत्तरवर्ती कंपनियों ने छत्तीसगढ़ राज्य व अलग मण्डल के गठन को सार्थक किया है। रजत जयंती वर्ष में भावी विकास की जो योजनाएं प्रस्तुत की गई है उससे बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

**▪ अजय सिंह**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल एवं पूर्व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली, प्रयास और उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य गठन और राज्य विद्युत मण्डल से कंपनियों में भी निरंतर बदलाव का लंबा दौर चला। अत्यंत गौरव का विषय है कि इस पूरे दौर में राज्य विद्युत मण्डल और उत्तरवर्ती कंपनियों ने चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बनाया और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान दिया। शासन की मंशा के अनुरुप पॉवर कंपनियों ने अधोसंरचना विकास के साथ ही समाज के हर वर्ग को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए जो योजनाएं बनाई है, उनकी सफलता की कामना करता हूं।

**▪ सुब्रत साहू**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़



अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में मैं बहुत लंबे समय तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए मुझे जो अनुभवों का भण्डार मिला उसे छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर राज्य के बंटवारे की जटिलताओं के बाद नए राज्य के नए विद्युत मण्डल को लेकर बहुत अधिक चुनौतियां, चिंताएं और आकांक्षाएं थीं। उस संक्रमण काल में अपने पुराने साथियों को साथ लेकर मैंने जो टीमवर्क किया वह बहुत संतुष्टि प्रदान करने वाला रहा। विद्युत विकास के माध्यम से राज्य के आर्थिक-सामाजिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने की भागीदारी को मैं जीवन की उपलब्धि मानता हूं। हमने मण्डल के संसाधनों से ही अधोसंरचना विकास के कार्य किए थे। किसी भी संस्था से ऋण नहीं लिया था। हम देश के पहले विद्युत मण्डल बने थे जिसमें विद्युत दर घटाने का निर्णय लिया गया था तथा कर्मचारियों के हित में करोड़ों रु. ग्रेच्युटी तथा पेंशन फंड में जमा कराए थे।

**▪ गोपाल तिवारी**

पूर्व अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ में होल्डिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शामिल थे जिसे बेहतर कार्य निष्पादन हेतु तीन कंपनियों में समायोजित किया गया। मुझे यह कहते हुए अच्छा लगता है कि हमारी विद्युत कंपनियों ने अपनी विरासत, नए राज्य की आवश्यकताओं, ऊर्जा क्षेत्र की भावी चुनौतियों को समझते हुए जिस कार्य संस्कृति का निर्माण किया है उसका लाभ प्रदेश की अन्य संस्थाओं को भी मिला है। देश की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत से यदि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत दोगुनी है तो इसका आशय है कि बिजली छत्तीसगढ़वासियों के जीवनस्तर उन्नयन और समग्र विकास का माध्यम बनी है।

**▪ अंकित आनंद**

पूर्व अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़



देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत स्टेट सेक्टर के विद्युत मण्डल, निगम तथा कंपनियों में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ को सर्वाधिक कार्य सक्षम, प्रतिभाशाली तथा परिणाम देने वाली संस्था के रूप में सम्मान के साथ देखा जाता है। केंद्र शासन की संस्थाओं तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा हमारी पॉवर कंपनियों को समय-समय पर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है। यही उत्कृष्टता बिजलीघरों पारेषण तथा वितरण कंपनियों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। वर्तमान में जो 32 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तंत्र के विकास हेतु करोड़ों रु. का पूंजी निवेश सुनिश्चित किया गया है उससे यह गारंटी मिली है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासियों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा।

**▪ पी. दयानंद**

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर
कंपनीज़ एवं पूर्व ऊर्जा सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद एक ओर जहां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन हुआ वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन भी हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ में भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इस प्रकार परम्परागत और गैर-परम्परागत ऊर्जा के विकास में मेरा योगदान दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में अब दोनों संभावनाओं पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की गारंटी है।

**▪ शैलेंद्र शुक्ला**

पूर्व अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़


₹14,300 करोड़
छत्तीसगढ़
रजत
महोत्सव
25

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती समारोह के अवसर पर 3752.87 करोड़ रुपये लागत की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल से किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की बहुआयामी प्रगति, उसमें ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व की सराहना की।



## लोकार्पण / समर्पण

| क्र. | निर्माण कार्य | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 400 केवी उपकेन्द्र ग्राम धरदेही जिला मुंगेली | 172.00 |
| 2 | 220 केवी उपकेन्द्र राजिम (गरियाबंद) एवं पाटन (दुर्ग) | 158.51 |
| 3 | 132 केवी उपकेन्द्र आरंग (रायपुर), टेमरी (बेमेतरा) मस्तुरी (बिलासपुर), जनकपुर (कोरिया) | 138.31 |
| 4 | 33 केवी उपकेन्द्र चोन्डीमेटवारा(बस्तर),जगरगुड़ा (सुकमा) | 10.42 |
| 5 | कृषि पंप के लिए 11 केवी लाइन | 633.42 |
| 6 | ओवर लोडेड 11 केवी फीडर विभाजन | 104.22 |
| 7 | अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना | 146.94 |
| 8 | ग्रामो में तार वाली एलटी लाइन केवी लगाने का कार्य | 903.64 |
| 9 | नई एलटी लाइन | 70.08 |



प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान साथ में मुख्यमंत्री श्री साय एवं नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री विकासशील

## शिलान्यास

| क्र. | निर्माण कार्य | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 220 केवी उपकेन्द्र पांडरवाही (कांकेर) | 84.00 |
| 2 | 132 केवी उपकेन्द्र, रोहरा (बलौदाबाजार-भाटापारा) | 58.64 |
| 3 | आरडीएसएस योजना अंतर्गत विद्युत आपूर्ति सुधार, कृषि पंप के लिए 11 केवी लाइन का निर्माण/ ओवर लोडेड 11 केवी फीडर का विभाजन / अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना | 1272.69 |




# प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से 2×660 मेगावॉट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट, कोरबा पश्चिम का कार्य प्रारंभ

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के इतिहास में 30 मार्च 2025 का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन के रूप में दर्ज हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2×660 मेगावॉट क्षमता के सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रारंभ बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्ठा में बटन दबाकर किया। इस अवसर पर श्री मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री श्री मोहनलाल खट्टर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा सहित प्रदेश के समस्त मंत्रीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डॉ. रोहित यादव भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के सभा स्थल पर प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार, श्री आरके शुक्ला तथा श्री भीमसिंह कंवर भी उपस्थित थे।



हमने आगामी 10 वर्षों की कार्य योजना बनाकर उस पर अमल प्रारंभ किया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रयासों को बहुत गंभीरता से लिया और राज्य शासन व एनटीपीसी के बिजली घरों के साथ ही अन्य वृहत्तर परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, कार्य आरंभ कराने के लिए छत्तीसगढ़ पधारे। इस तरह 30 मार्च 2025 का दिन छत्तीसगढ़ के विकास के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है।

**▪ विष्णु देव साय**
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़











# रजत जयंती वर्ष में 32 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन तथा पारेषण, वितरण परियोजनाओं हेतु पूंजी निवेश के एमओयू

- **परमाणु ऊर्जा** – छत्तीसगढ़ में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी द्वारा साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें 700 मेगावॉट की छह यूनिट लगाने की योजना है। इस तरह कुल 4200 मेगावॉट के परमाणु संयंत्र लगेंगे।
- **ताप विद्युतः** – राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए 1,07,840 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन




मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उच्चतम प्राथमिकता और विशेष प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 32 हजार मेगावॉट स्थापित क्षमता के बिजलीघर स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 10 मार्च को छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन रायपुर में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और छत्तीसगढ़ की आगामी 10 वर्षों की बिजली मांग को देखते हुए व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। जिसके तहत आगामी 5-6 वर्षों में अतिरिक्त 31 हजार मेगावॉट से अधिक की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं। बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्र में आगामी वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश को सरप्लस पॉवर स्टेट का जो गौरव प्राप्त है उसे स्थाई रखने और आगे बढ़ाने की दिशा में विद्युत विकास की व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है।

कंपनी 660-660 मेगावॉट के दो सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना कोरबा में स्थापित करने जा रही है। इस 1320 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र की लागत 15800 करोड़ रुपए होगी। इसी तरह एनटीपीसी लारा (रायगढ़) में 1600 मेगावॉट और सीपत में 800 मेगावॉट क्षमता का संयत्र लगाएगी।

निजी क्षेत्र से अडानी पॉवर 1600-1600 मेगावॉट के तीन संयंत्र कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में तथा 1320 मेगावॉट का संयंत्र कोरबा में लगाएगी। जिंदल पॉवर 1600 मेगावॉट और सारडा एनर्जी



660 मेगावॉट का संयंत्र रायगढ़ में स्थापित करेगी।

- **सौर ऊर्जा** – सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हैं, जिनमें एनटीपीसी और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी मिलकर दो हजार मेगावॉट तथा जिंदल पॉवर डोलेसरा रायगढ़ में 500 मेगावॉट का सोलर पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करेगी।
- **पंप स्टोरेज परियोजनाएं** – छत्तीसगढ़ में नई तकनीक से किफायती और सस्ती बिजली उत्पादन के लिए पंप स्टोरेज पॉवर संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें विभिन्न जलाशयों के पानी का कई बार उपयोग करते हुए बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में 58,046 करोड़ के निवेश की योजना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी हसदेव बांगो जलाशय में 800 मेगावॉट और रौनी में 2100 मेगावॉट के दो पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने एनएचपीसी के सहयोग से सिकासेर में 1000 मेगावॉट, एनटीपीसी के सहयोग से 1200 मेगावॉट, सतलज जल विद्युत निगम कोटपल्ली में 1800 मेगावॉट, टिहरी हाइडल डेवलपमेंट कार्पोरेशन डोंगरी में 1400 मेगावॉट के पंप स्टोरेज संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। निजी क्षेत्र जिंदल रिनोवेबल पॉवर 3000 मेगावॉट और रिन्यू विद्युत तेज 2000 मेगावॉट क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट लगाने जा रही है।
- **क्रेडा सौर पहल:**– क्रेडा के जरिये 108 परियोजनाओं पर निजी क्षेत्र ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड पीवी इन्वेस्टमेंट के तहत कार्य कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा विस्तार के लिए 3,200 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।
- **पीएम कुसुम योजना:**– किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधामंत्री कुसुम योजना संचालित है, जिसके तहत क्रेडा 4,100 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम कर रही है।
- **पीएम सूर्यघर योजना:**– प्रदेश के छह लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है, 1200 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल घर की छतों में लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है। साथ ही सरकारी और निजी भवनों में 500 मेगावॉट के सोलर संयंत्र लगाने की योजना अगले पांच सालों में बनाई गई है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
- **सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा:** सरकारी और निजी इमारतों में 500 मेगावॉट के सौर पैनल लगाने का प्रस्ताव है। आगामी पांच वर्षों में 2,500 करोड़ का निवेश होगा।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली:** छत्तीसगढ़ शासन और सेकी ने भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोर पॉवर प्लांट (40 मेगावॉट) की स्थापना राजनांदगांव में की है। इससे 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। भविष्य में इस तरह के और संयंत्र लगाने के लिए 2,600 करोड़ का निवेश होगा।
- **पॉवर ट्रांसमिशन नेटवर्क** – प्रदेश में उत्पादित बिजली को उपकेंद्रों तक गुणवत्ता के साथ पहुंचाने के लिए बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने जा रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी 13,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।
- **आरडीएसएस (वितरण क्षेत्र योजना)** – रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वृहद कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें 11 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- **मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना** – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इस योजना के तहत 1585 करोड़ रुपए के कार्य कराये जाएंगे।

# चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सफरनामा

छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां प्रदेश बना। राज्य की स्थापना के तत्काल पश्चात 15 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) की अधिसूचना क्रमांक 18 एवं 22/उवि/2000, 15 नवम्बर 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1948 (1948 का सांख्यक-54 की धारा एक की उपधारा (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया है। तदोपरांत 1 दिसम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने विधिवत अपना कार्य शुरू किया।

नए राज्य का अपना अलग विद्युत मण्डल होगा या नहीं होगा इसे लेकर बहुत सी चर्चाएं थी लेकिन अंततः छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन तत्काल प्रभाव से होगा। इस तरह राज्य गठन के पंद्रहवें दिन अर्थात 15 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के प्रथम अध्यक्ष के पद पर श्री सुयोग्य कुमार मिश्र, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ श्री बी.के.एस. रे, कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को तारीख 15 नवम्बर 2000 से सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। इस तरह 1 दिसंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की कुल उत्पादन क्षमता के अलावा केंद्रीय क्षेत्र से मिलने वाले हिस्से को मिलाकर छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो गई थी लेकिन पारेषण तथा वितरण तंत्र की स्थिति बेहद खराब होने के कारण प्रारंभिक दिनों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।


वर्ष 1928 : भाटागांव, रायपुर में इस डीजी सेट से होती थी जल आपूर्ति

पारेषण तथा वितरण तंत्र को सक्षम बनाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। राज्य गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 2003 के अंत में हुआ। जिसमें डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में विद्युत विकास के लिए बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रयासों का नया दौर वास्तव में वर्ष 2003 के पश्चात ही शुरू हुआ। इस बीच विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2 (55) के तहत पश्चिमी क्षेत्र विद्युत मण्डल में भी बदलाव हुआ और वेस्टर्न रीजन पॉवर कमेटी (डब्ल्यूआरपीसी) का गठन हुआ, जो केंद्र शासन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और सदस्य राज्यों के बीच समन्वयक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए तैयारी की गई। वेस्टर्न रीजन में छत्तीसगढ़ के साथ अन्य सदस्य राज्य हैं- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव।

बस्तर संभाग में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए 25 सितंबर 2009 को संपन्न डब्ल्यूआरपीसी की बैठक में जगदलपुर को उड़ीसा के अति उच्चदाब सिस्टम से जोड़ने की पहल की गई।

## राज्य गठन में प्राप्त छत्तीसगढ़ के विद्युत गृह

| क्र. | विद्युत गृहों के नाम | इकाइयां | स्थापित क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1. | कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा (पूर्व) | 2×120 मेगावॉट + 4×40 मेगावॉट | 400 मेगावॉट |
| 2. | हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पश्चिम) | 4×210 मेगावॉट | 840 मेगावॉट |
| | **कुल ताप विद्युत गृह** | | **1240 मेगावॉट** |
| 3. | हसदेव बांगो जल विद्युत गृह माचाडोली | 3×40 मेगावॉट | 120 मेगावॉट |
| 4. | लघुकृत जल विद्युत गृह, रुद्री | 1×1.2 मेगावॉट | 1.2 मेगावॉट |
| | **कुल जल विद्युत क्षमता** | | **121.2 मेगावॉट** |
| | **कुल ताप + जल** | | **1361.2 मेगावॉट** |

## इकाईवार स्थापित क्षमता एवं परिचालन तिथि

| विद्युत गृह | इकाई क्रमांक | स्थापित क्षमता (मेगावॉट) | परिचालन तिथि |
|---|---|---|---|
| ताप विद्युत गृह | | | |
| कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह | संकुल | 540 | |
| विद्युत गृह क्रमांक 1 | कुल | 100 | |
| | प्रथम इकाई | 30 | 1 मार्च 1959 |
| | द्वितीय इकाई | 30 | 27 जुलाई 1959 |
| | तृतीय इकाई | 30 | 31 मार्च 1960 |
| | चतुर्थ इकाई | 10 | 31 अक्टूबर 1963 |
| विद्युत गृह क्रमांक 2 | कुल | 200 | |
| | प्रथम इकाई | 50 | 22 अक्टूबर 1966 |
| | द्वितीय इकाई | 50 | 16 जुलाई 1967 |
| | तृतीय इकाई | 50 | 28 मार्च 1968 |
| | चतुर्थ इकाई | 50 | 31 अक्टूबर 1968 |
| विद्युत गृह क्रमांक 3 | कुल | 240 | |
| | प्रथम इकाई | 120 | 24 मार्च 1976 |
| | द्वितीय इकाई | 120 | 5 अप्रैल 1981 |
| डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व | संकुल | 500 | |
| | प्रथम इकाई | 250 | 21 अक्टूबर 2007 |
| | द्वितीय इकाई | 250 | 20 मार्च 2008 |
| हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम | संकुल | 840 | |
| | प्रथम इकाई | 210 | 21 जून 1983 |
| | द्वितीय इकाई | 210 | 30 मार्च 1984 |
| | तृतीय इकाई | 210 | 26 मार्च 1985 |
| | चतुर्थ इकाई | 210 | 13 मार्च 1986 |
| कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र | प्रथम इकाई | 500 | 5 सितम्बर 2013 |
| अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर-चांपा | संकुल | 1000 | |
| | प्रथम इकाई | 500 | 31 मार्च 2016 |
| | द्वितीय इकाई | 500 | 31 जुलाई 2016 |
| | कुल ताप विद्युत | 3380 | |
| जल विद्युत गृह हसदेव बांगो जल विद्युत गृह | संकुल | 120 | |
| | प्रथम इकाई | 40 | 21 मार्च 1994 |
| | द्वितीय इकाई | 40 | 21 नवंबर 1994 |
| | तृतीय इकाई | 40 | 11 जनवरी 1995 |
| कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह | संकुल | 1.7 | |
| | प्रथम इकाई | 0.85 | 12 जनवरी 2003 |
| | द्वितीय इकाई | 0.85 | 4 जुलाई 2009 |
| गंगरेल जल विद्युत गृह | संकुल | 10 | |
| | प्रथम इकाई | 2.5 | 28 जुलाई 2004 |
| | द्वितीय इकाई | 2.5 | 4 अगस्त 2004 |
| | तृतीय इकाई | 2.5 | 3 मई 2005 |
| | चतुर्थ इकाई | 2.5 | 23 मई 2005 |
| सिकासार जल विद्युत गृह | संकुल | 7 | |
| | प्रथम इकाई | 3.5 | 3 सितंबर 2006 |
| | द्वितीय इकाई | 3.5 | 3 सितंबर 2006 |
| | कुल जल विद्युत | 138.70 | |
| सह-उत्पादन (को-जन), भोरमदेव कवर्धा | प्रथम इकाई | 6 | 10 अगस्त 2006 |
| छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंमनी (ताप, जल, अन्य विद्युत गृह) | | 3524.70 | |

- छत्तीसगढ़ में कुल 3524.70 मेगावाट क्षमता के बिजलीघर स्टेट सेक्टर में स्थापित हुए। कालांतर में कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्र. 1 की 100 मेगावाट की इकाइयां वर्ष 1989 में सेवानिवृत्त हुई।
- कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्र. 2 की 200 मेगावाट की इकाइयां 14 सितंबर 2018 में सेवानिवृत्त हुई।
- कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्र. 3 की 240 मेगावाट की इकाइयां 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुई।
- सह-उत्पादन (को-जन), भोरमदेव कवर्धा की 6 मेगावाट क्षमता वाली इकाई को भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा को 31 मार्च 2022 को हस्तांतरित किया गया।
- इस प्रकार 546 मेगावाट की इकाइयां सेवानिवृत्त होने से 3524.70 मेगावाट की स्थापित क्षमता में से 2978.70 मेगावाट की स्थापित क्षमता शेष रह गई जो वर्तमान में विद्यमान है।










## वर्ष 2009 में बनी 5 स्टेट पॉवर कंपनीज़.

विद्युत अधिनियम 2003 के परिपालन में 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को 5 अलग-अलग विद्युत कंपनियों में विभाजित किया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गठन किया गया।

## वर्ष 2022 में बनी 3 स्टेट पॉवर कंपनीज़

अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में समाहित कर दिया गया। इस तरह अगस्त 2022 से छत्तीसगढ़ में 5 की जगह सिर्फ 3 कंपनियां- उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए कार्यरत हैं।


डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व का लोकार्पण


वर्ष 2004 : गंगरेल में लघु जल विद्युत गृह का लोकार्पण




## 2 दशक बाद स्टेट सेक्टर का ताप बिजलीघर

वर्ष 1986 में हसदेव ताप विद्युत गृह की 210 मेगावॉट की चौथी इकाई 13 मार्च 1986 को क्रियाशील हुई थी। उसके बाद नए बिजलीघर स्थापित होने का सिलसिला वर्ष 2007 से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन की रणनीति पर विचार किया गया। उनके पहले कार्यकाल (2003-2008) में उनके सघन प्रयासों और नियमित मॉनीटरिंग के कारण 30 मार्च 2007 तथा 11 दिसंबर 2007 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पॉवर स्टेशन, कोरबा पूर्व में 250-250 मेगावॉट की 2 इकाइयां स्थापित की गई। इस बीच छोटे-छोटे जल विद्युत गृहों की भी संभावनाओं को साकार किया गया। कोरबा पश्चिम में लघु जल विद्युत गृह की 0.85-0.85 मेगावॉट की दो इकाइयां (कुल 1.7 मेगावॉट) क्रमशः 12 जनवरी 2003 और 4 जुलाई 2009 को क्रियाशील हुई।

गंगरेल में 2.5-2.5 मेगावॉट की चार इकाइयां (कुल 10 मेगावॉट) क्रमशः 28 जुलाई 2004, 4 अगस्त 2004, 3 मई 2005, 23 मई 2005 को क्रियाशील की गई। इसी प्रकार सिकासार में 3.5-3.5 मेगावॉट की दो इकाइयां (कुल 7 मेगावॉट) 3 सितंबर 2006 को क्रियाशील की गई। इसके अलावा भोरमदेव स्थित शक्कर कारखाने में 6 मेगावॉट की एक को-जनरेशन इकाई 10 अगस्त 2006 को क्रियाशील की गई। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दूसरे कार्यकाल (2008-2013) में प्रदेश में दूसरी ताप विद्युत परियोजना हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम की 500 मेगावॉट की इकाई 22 मार्च 2013 को क्रियाशील की गई। उनके तीसरे कार्यकाल (2013-2018) में स्टेट सेक्टर की तीसरी परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर चांपा की 500-500 मेगावॉट की दो इकाइयां भी 31 मार्च 2016 को क्रियाशील की गई। इस बीच सेंट्रल सेक्टर व निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना का कार्य तेजी से हुआ।

सेंट्रल सेक्टर में स्थापित होने वाले बिजलीघरों से राज्य को अधिकाधिक हिस्सा दिलाने के लिए भी डॉ. रमन सिंह द्वारा कुशल रणनीति से कार्य किया गया। सामान्य प्रक्रिया अनुसार सेंट्रल सेक्टर के बिजलीघर जब किसी राज्य में स्थापित होते है तो वहां उत्पादित बिजली का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य को मिलता है। लेकिन डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में एनटीपीसी लारा बिजलीघर की स्थापना के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के संसाधनों के मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से उठाया और एनटीपीसी लारा में उत्पादित बिजली से 50 प्रतिशत हिस्से की मांग सामने रख दी। इस अभियान में मिली सफलता बेहद महत्वपूर्ण है। जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को दीर्घकाल तक मिलेगा।

किसी नए ताप बिजलीघर की स्थापना में कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में न सिर्फ नए बिजलीघर लगाने के बारे में विचार किया गया बल्कि उसे अमल में लाने के लिए समुचित कदम भी उठाए गए। जिसके कारण प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की कुल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2840 मेगावॉट तथा जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.70 मेगावॉट है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर



हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम

जनरेशन कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 2978.70 मेगावॉट है। उल्लेखनीय है कि कोरबा ताप विद्युत गृह की 50-50 मेगावॉट की चार इकाइयां तथा 120-120 मेगावॉट की दो इकाइयां अर्थात 440 मेगावॉट की इकाइयां अत्यधिक पुरानी होने के कारण सेवानिवृत्त कर दी गई हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी वर्ष 2016-17 में 3424.70 मेगावॉट के साथ अब तक की सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंची थी जो अब वर्तमान में 2978.70 मेगावॉट पर स्थिर है। इस क्रम में 30 मार्च 2025 का दिन एक नए कीर्तिमान की तरह दर्ज हुआ है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के पहले सुपर क्रिटिकल पॉवर थर्मल पॉवर स्टेशन (660-660 मेगावॉट) की दो इकाइयां के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।

# विद्युत उत्पादन क्षमता - तब और अब

| विवरण | तब (वर्ष 2000) | अब (वर्ष 2025) | 25 वर्षों की उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| स्थापित क्षमता (मेगावॉट) | 1,360 | 2,978.70 | 1,618.70 |
| प्रस्तावित क्षमता | 0 | 32 हजार मेगावॉट में पृथक-पृथक भागीदारी | |



डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व



एशिया का सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट जो कोयला खदान कुसमुंडा से 14.5 किलोमीटर दूर कोरबा के बिजली घरों तक कोयला पहुंचाता है



अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा


खदान से बिजली घर तक कोयला परिवहन : कन्वेयर बेल्ट


ताप विद्युत गृह : कोल हेन्डलिंग


हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, माचाडोली


लघु जल विद्युत गृह, गंगरेल

## लीक से अलग हटकर कोयला खदान संचालन का कार्य, उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को तहसील तमनार जिला रायगढ़ में स्थित गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान आबंटित किया गया है, जिसका सभी मापदण्डों को पूरा करते हुए सफलता पूर्वक संचालन दिनांक 06.12.2019 से किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन अनुसार उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से अब तक निर्धारित समय-सीमा में सुरक्षा के मापदण्डों की पूर्ति करते हुए निर्धारित कोयला उत्पादन लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है एवं कोयला उत्पादन का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में गारे पेलमा-III कोयला खदान द्वारा निर्धारित लक्ष्य 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक 40.02 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया गया। उल्लेखित है कि गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान से वर्ष 2024-25 में माह जुलाई तक कुल 135.6998 लाख मीट्रिक टन कोयले का खनन एवं 134.449 लाख मीट्रिक टन कोयले का परिवहन छ. ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के ताप विद्युत गृहों को किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर कोल संकट के समय में भी कोयला उत्पादन एवं परिवहन का कार्य अनवरत रूप से किया गया जिससे प्रदेश में निर्बाधित रूप से बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति का कार्य संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, शून्य दुर्घटना, श्रमिक कल्याण गतिविधियों तथा धूल नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यो के लिए वर्ष 2020 में तीन पुरस्कार एवं वर्ष 2021 में चार पुरस्कार प्राप्त हुए है। जिसमें इन पुरस्कारों में वर्ष 2021 के लिए Overall Perfomance के लिए 30 लाख टन की खुली खदानों के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। गारे पेलमा सेक्टर-III माईन को खुली खदान की "E" श्रेणी में वार्षिक कोल माईन पखवाड़ा 2023 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों हेतु वर्ष 2023 में 5 अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।



## छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की माह अप्रैल की रिपोर्ट अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देशभर के विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 69.07 प्रतिशत रहा वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 84.45 प्रतिशत पी.एल.एफ. के साथ स्टेट सेक्टर में प्रथम स्थान पर होने का कीर्तिमान हासिल किया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (मड़वा) द्वारा सर्वकालिक 84.11 प्रतिशत पी.एल.एफ. के साथ सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन 7388.54 मिलियन यूनिट एवं सर्वकालिक न्यूनतम ऑक्जिलरी खपत 5.01 प्रतिशत, सर्वकालिक न्यूनतम विशिष्ट तेल खपत 0.156 मि.ली. / यूनिट प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित किया।

हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में लॉन्ग डिस्टेन्स कोल कन्वेयर (LDCC) के माध्यम द्वारा एस.ई.सी. एल. के 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नये कोल बंकर से कोयले की आपूर्ति 24 दिसम्बर 2019 से प्रारंभ की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी को मेसर्स मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा "Best Water Management & Ash handling" 2021 esa Winner एवार्ड प्राप्त हुआ।



रजत जयंती वर्ष में प्रदेश का पांचवा 400 केवी उपकेन्द्र धरदेही (जिला मुंगेली में) क्रियाशील किया जाना कंपनी की निरंतर क्रियाशीलता का प्रतीक है। पारेषण तंत्र का उन्नयन और विस्तार प्रदेश की विद्युत प्रणाली को स्थायित्व व विश्वनीयता प्रदान करता है। विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे अथक प्रयास छत्तीसगढ़ के सुरक्षित भविष्य की गारंटी साबित होंगे।

▪ **सुबोध कुमार सिंह** IAS
अध्यक्ष- सीएसपीटीसीएल

# पारेषण क्षमता विकास गुणवत्ता का विश्वास









गौरवान्वित छत्तीसगढ़ : देश का पहला एचवीडीसी स्टेशन, बारसूर

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय अर्थात 1 नवम्बर 2000 की स्थिति में प्रदेश की पारेषण प्रणाली में ट्रांसफार्मरों की क्षमता मात्र 3,552 एमवीए थी, जो सितम्बर 2025 तक 683.22 प्रतिशत बढ़कर 27,820 एमवीए हो गई। 26 जुलाई, 2025 को 400 केवी क्षमता का पांचवा उपकेन्द्र धरदेही जिला मुंगेली में ऊर्जीकृत किया गया। इसके पहले वर्ष 2020 में कुरूद जिला धमतरी में 400 केवी का विद्युत उपकेन्द्र क्रियाशील किया गया था।

अब प्रदेश में 400 केवी उपकेन्द्रों की संख्या 1 से बढ़कर 5, इस क्षमता के ट्रांसफार्मरों की संख्या 3 से बढ़कर 14, 220 केवी उपकेन्द्रों की संख्या 5 से बढ़कर 27, इस क्षमता



गौरवान्वित छत्तीसगढ़ : प्रदेश का पांचवा 400 केवी उपकेन्द्र, धरदेही

के ट्रांसफार्मरों की संख्या 12 से बढ़कर 72, 132 केवी उपकेन्द्रों की संख्या 20 से बढ़कर 105 तथा इस क्षमता के ट्रांसफार्मरों की संख्या 46 से बढ़कर 284 हो गई है। इसी प्रकार 400 केवी लाइनों की लंबाई 277 से बढ़कर 1938 सर्किट किलोमीटर, 220 केवी लाइनों की लंबाई 1594 से बढ़कर 4383 सर्किट किलोमीटर तथा 132 केवी लाइनों की लंबाई 2974 से बढ़कर 8395 सर्किट किलोमीटर हो गई है। पारेषण क्षमता में विकास की कहानी अत्यंत उत्साहजनक है।

अन्य राज्यों में उपलब्ध तथा उत्पादित बिजली प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय ग्रिड से हस्तांतरण क्षमता (अवैलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी-एटीसी) बढ़ाने की बड़ी भूमिका होती है। राज्य गठन के समय यह क्षमता नगण्य थी जो अब बढ़कर 4930 मेगावॉट हो गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ 6000 मेगावॉट एटीसी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार की उदार नीतियों के कारण एक ओर जहां एनटीपीसी तथा निजी विद्युत उत्पादकों ने तेजी से कार्य किया, वहीं दूसरी ओर पॉवर ग्रिड

कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पारेषण क्षमता बढ़ाने की दिशा में योगदान दिया गया।

## अंतरराज्यीय संयोजकता

देश में विद्युत पारेषण के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसे राष्ट्रीय ग्रिड (वन नेशन-वन ग्रिड) के नाम से जाना जाता है। इसका संचालन पॉवर ग्रिड आफ कार्पोरेशन करती है। देश में किसी भी राज्य में बिजली पैदा होती हो, उसे पहले नेशनल ग्रिड में डाला जाता है, जिसके बाद अपनी मांग और आबंटन के हिसाब से हर राज्य उसे उपयोग में लेते हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड को पांच क्षेत्रीय ग्रिड में विभाजित किया गया है, छत्तीसगढ़ वैसे तो देश के पश्चिम क्षेत्रीय (वेस्टर्न रीजन ग्रिड) विद्युत मंडलों में शामिल है तथा इसके सदस्य राज्यों के साथ अंतरराज्यीय पारेषण संयोजकता (कनेक्टिविटी) बनाये हुए है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से तीन राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और ओड़िशा से 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी लाइनों से जुड़ा हुआ है। खेदामारा (भिलाई) 400 केवी उपकेंद्र से महाराष्ट्र के 400 केवी भद्रावती और कोराड़ी से जुड़ा है।

वहीं खेदामारा उपकेंद्र मध्यप्रदेश के 400 व 132 केवी किरनापुर और 220 केवी अनूपपुर से जुड़ा है। साथ ही छत्तीसगढ़ कोरबा 220 केवी उपकेंद्र से ओड़िशा के 220 केवी बूढ़ीपढ़ार एवं जगदलपुर के 400 उपकेंद्र से 400 केवी डबल सर्किट ज्योपुर (ओड़िशा) से जुड़ा है। इस तरह पश्चिम ग्रिड में आने वाला छत्तीसगढ़ पूर्वी ग्रिड से भी अंतरराज्यीय संयोजकता बनाए हुए है।

## हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी)

बिजली के उच्च वोल्टेज पर लंबी दूरी तक पारेषण के लिए पहले सीमित क्षमता में ही काम किया जाता था और अल्टरनेटिंग करेंट से ही ज्यादातर पारेषण होता था। वास्तव में अल्टरनेटिंग करेंट से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का माध्यम है। काफी लंबे समय तक इसी माध्यम का उपयोग बिजलीघरों से 132 और 220 केवी उपकेन्द्रों और उसके बाद





गौरवान्वित छत्तीसगढ़ : प्रदेश का पहला 132 केवी गैस आधारित उपकेन्द्र

वितरण ट्रांसफार्मरों को बिजली प्रदाय करने के लिए किया जाता था।

उस दौर में अविभाजित मध्यप्रदेश में ताप विद्युत गृहों की अधिकता थी जबकि आंध्रप्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन अधिक होता था। दोनों राज्यों के बीच विद्युत प्रणाली के आदर्श समन्वय एवं विद्युत मांग की पूर्ति हेतु यह आदान-प्रदान वर्ष में कुछ महीनों के लिए ही किया जाता रहा। जिससे यह परियोजना कालान्तर में वायबल नहीं रह पाई।

एसी प्रणाली में सबसे बड़ी दिक्कत समान फ्रिक्वेंसी पर सिंक्रोनाइजेशन की होती थी। कई बार तो फ्रिक्वेंसी मैच कराने पर घंटों का समय लगता था और लोड सेंटर पर समुचित विद्युत प्रदाय में बाधा आती थी। देश में विद्युत पारेषण की नई तकनीक का विकास एचवीडीसी (हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट) कनवर्टर स्टेशन के रूप में हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बारसूर है। इस प्रोद्यौगिकी को स्वीडन स्थित अंतरराष्ट्रीय कंपनी एशियन ब्राउन ब्रोवेरी (एबीबी) से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ओर से नेशनल एचवीडीसी संस्था का गठन किया गया है। जिसके लीड पार्टनर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) सहित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरई), आंध्रप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल बने। एचवीडीसी का उपयोग अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र के विकास में करने की आवश्यकता को देखते हुए शोध और विकास के उद्देश्य से यह पहल की गई।

वास्तव में यह भिन्न-भिन्न ग्रिड को जोड़ने वाली परियोजना थी जिसके लिए बतौर सावधानी यह व्यवस्था जरूरी थी कि प्रयोग के विफल हो जाने पर भी पारेषण तंत्र के संचालन में जटिलता उत्पन्न न हो। अविभाजित मध्यप्रदेश के बारसूर (बस्तर जिला) में स्थित तथा आंध्रप्रदेश के लोवर सिलेरू (राजमुंदरी जिला) के मध्य 220 केवी की 196 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय लाइन को इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा गया। जिसमें सामान्यतः पॉवर ट्रांसफर निरंतर नहीं होता था।

उल्लेखनीय है कि यह पारेषण लाइन सदर्न ग्रिड तथा वेस्टर्न ग्रिड को जोड़ने का काम करती थी। जिसमें आवश्यकतानुसार आंध्रप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में बिजली का आदान-प्रदान होता था। परियोजना के लिए तय कार्यक्रम अनुसार इसे तीन चरणों में करने का लक्ष्य रखा गया था।

प्रथम चरण में 100 केवी - 100 मेगावॉट, द्वितीय चरण में 200 केवी - 200 मेगावॉट तथा तीसरे चरण में प्लस/माइनस 200 केवी - 400 मेगावॉट की परियोजना स्वीकृत की गई। तदनुसार वर्ष 1986 में कार्य प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1989 में प्रथम चरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वर्ष 1996 में द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ हुआ और 1999 में पूर्ण हुआ। इस तरह प्रथम चरण में एचवीडीसी के माध्यम से 100 मेगावॉट और द्वितीय चरण में 150 मेगावॉट तक पॉवर के पारेषण में सफलता प्राप्त की गई।

एचवीडीसी पारेषण का मुख्य लाभ यह है कि अल्टरनेटिव करेंट की तुलना में डायरेक्ट करेंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती अतः यह दो ग्रिडों को सिंक्रोनाइज करने की जटिलता का स्थायी समाधान है। इसमें पॉवर ट्रांसफर की मात्रा में नियंत्रण संभव है। एसी के तीन तार के विरूद्ध डीसी का एक तार ही कारगर होता है। इस तरह कॉपर या एल्युमिनियम की मात्रा सहित पारेषण के उपयोग में आने वाले टावर के लोहे में अच्छी खासी बचत होती है। एसी की तुलना में डीसी प्रणाली में पर्यावरण की मदद होती है क्योंकि इसमें टॉवरों की संख्या कम होने के कारण पेड़ों की कटाई अपेक्षाकृत कम होती है।



कर्मकौशल : 400 केवी टॉवर पर कार्यरत लाइन स्टाफ




# स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, डंगनिया, रायपुर

अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में स्थित था तब मध्यप्रदेश का लोड डिस्पैच सेंटर, भार प्रेषण केंद्र भी जबलपुर में ही था, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में भी (भार प्रेषण केंद्र) विद्युत उत्पादन व आपूर्ति की मानीटरिंग की जाती थी।

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तथा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से विभाजन उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवम्बर 2000 में हुआ। इस विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य भार प्रेषण केन्द्र का सुचारू रूप से संचालन करना। राज्य गठन के एक माह उपरांत ही इस हेतु 400 केवी सबस्टेशन, खेदामारा भिलाई, के परिसर में 1 दिसम्बर 2000 से राज्य भार प्रेषण केंद्र ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2009 में भार प्रेषण केन्द्र का स्थायी भवन राज्य मुख्यालय डंगनिया रायपुर में बनाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। खेदामारा से एसएलडीसी को रायपुर में निर्मित नए और आधुनिक जरूरतों के अनुकूल विकसित भवन में जनवरी 2012 में स्थानांतरित किया गया। वहीं खेदामारा में वर्ष 2016 में नए भवन में बैकअप एसएलडीसी का संचालन शुरू किया गया।

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन किसी सरकारी कम्पनी या किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जब तक किसी सरकारी कंपनी या किसी प्राधिकरण या निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी राज्य भार प्रेषण केंद्र का संचालन करेगी। यह भी प्रावधान है कि कोई भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत के व्यापार में संलग्न नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड का एक घटक है। अन्य राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, दमन और दीव सहित सभी राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों को मुंबई स्थित पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पेच केंद्र के निर्देशों का पालन करना होता है।

पश्चिमी क्षेत्र को देश में सबसे पहले 2002 से केंद्रीय क्षेत्र के बिजली तारों के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ एबीटी लागू करने का गौरव प्राप्त है, जिसके बाद ग्रिड संचालन में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही, बिजली की अधिकता अथवा कमी के आधार पर अंतरक्षेत्रीय बिजली व्यापार शुरू हो गया। ऐसे में एसएलडीसी की जिम्मेदारी अधिक थी कि कोई भी लाइन ओव्हर लोड न होने पाए, साथ ही उत्पादित हर एक यूनिट बिजली का लेखा-जोखा रखा जिससे उत्पादक, पारेषण और उपभोक्ता के बीच पारदर्शी लेन-देन की व्यवस्था बनी रहे। आज एसएलडीसी से 217 इकाइयाँ पंजीकृत हैं जिसमें 61 कैप्टिव पॉवर प्लांट भी शामिल हैं। इसलिए लोड डिस्पैच सेंटर की भूमिका इस बिजली के व्यापार में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वी क्षेत्र, जो उस समय बिजली अधिशेष वाले राज्यों का समूह था, को वर्ष 2003 से नवस्थापित 400 केवी राउरकेला-रायपुर (पीजीसीआईएल) डबल सर्किट लाइन के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र के साथ समन्वित किया गया। इससे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों को अतिरिक्त बिजली का हस्तांतरण संभव हो पाया और आवृत्ति प्रोफ़ाइल में सुधार हुआ।

वर्तमान में एसएलडीसी राज्य के विभिन्न सब स्टेशनों के साथ-साथ राज्य में केंद्रीय क्षेत्र की 28 ड्रावल पॉइंट से जुड़ा हुआ है और मुख्यालय में कंपनी प्रमुखों को 09 सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्काडा टर्मिनलों की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन 20 अप्रैल 2005 का दिन रहा, जब केंद्रीय ग्रिड जो उत्तर.पूर्व, पूर्व और पश्चिम राज्यों के बीच भूमिका निभा रहा है को 400 केवी गोरखपुर-मुजफ्फरपुर डबल सर्किट लाइनों के माध्यम से उत्तरी ग्रिड के साथ समन्वित किया गया। वर्ष 2007 से पारेषण लाइनों की खुली पहुंच की शुरूआत की गई और अब एसएलडीसी अल्पावधि खुली पहुंच के लिए नोडल एजेंसी है।

## पारेषण तंत्र की प्रगति, श्रेष्ठता का इतिहास

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के जमाने से ही ट्रांसमिशन विंग की कार्यकुशलता, दक्षता तथा नवाचार देश में अग्रणी स्थान रखते थे। इस तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को अपने श्रेष्ठ अभियंताओं तथा तकनीकी कर्मचारियों की वजह से बढ़त हासिल थी। यही वजह है कि एचवीडीसी जैसे प्रयोग का गौरव छत्तीसगढ़ को मिला। राज्य गठन के बाद कंपनी को नई प्रोद्यौगिकी अपनाने और तेजी से विकास के जो अवसर मिले उसे परिणाम में बदलने में हम सफल रहे।

वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 132 केवी गैस आधारित (जी. आई.एस.)उपकेन्द्र, रावण भाटा (रायपुर) के डिजाइनिंग, निर्माण तथा ऊर्जीकरण कार्यों में पारेषण कंपनी के नवाचार के दर्शन होते है। इस तकनीक पर अब 3 नग 400 केवी एवं 1 नग 132 केवी उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है, जो 10 वर्षों पूर्व हासिल की गई सफलता की आज भी प्रासंगिकता का प्रतीक है। पारेषण कंपनी द्वारा किये गये इस तरह के नवाचारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। छत्तीसगढ़ का पहला 132 केवी अंडरग्राउड केबल 220 केवी उपकेन्द्र डोमा एवं रावणभाटा (रायपुर) के मध्य वर्ष 2016 में संचालित किया गया। 220 केवी मल्टीसर्किट टॉवर लाइन (मोपका-धरदेही-भाटापारा-सिलतरा) का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया है। अभी शहर के सघन जनसंख्या एवं सघन वन वाले इलाकों में मल्टी सर्किट टॉवरों का उपयोग लगभग सभी लाइनों पर किया जा रहा है। 14 नग 132 केवी लाइनों के पुराने कंडक्टरों (तारों) को उच्च क्षमता के एचटीएलएस कंडक्टरों से बदलने का कार्य किया गया है एवं 3 नग पारेषण लाइनों में कंडक्टर बदलने का कार्य प्रगति पर है।


400 केवी सिंगल सर्किट लाइन

लगभग 5335 किलोमीटर लंबी उच्चदाब पारेषण लाइनों में जीआई अर्थ वायर को ऑप्टिक फाइबर ग्राउंड वायर में बदलने का कार्य पूर्ण करवाने में भी पारेषण कंपनी ने सफलतापूर्वक कार्य किया। यह आधुनिकतम संचार प्रणाली द्वारा ईएचटी उपकेंद्रों व भार प्रेषण केंद्र के बीच रीयल टाइम डेटा ट्रांसफर में मदद करती है। पहली बार 400 केवी रायता-कुरूद व रायता-जगदलपुर चालू लाइनों में रायपुर-विशाखापट्टनम हाईवे के निर्माण हेतु टॉवर शिफ्टिंग व हाईट रेजिंग का कार्य ई.आर.एस.



## पारेषण अधोसंरचना - तब और अब

| विवरण | वर्ष 2000 | वर्ष 2025 | 25 वर्षों की उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| उपकेंद्रों की संख्या | 26 नग | 137 नग | 111 नग |
| 400 केवी उपकेंद्र | 1 नग | 5 नग | 4 नग |
| 220 केवी उपकेंद्र | 5 नग | 27 नग | 22 नग |
| 132 केवी उपकेंद्र | 20 नग | 105 नग | 85 नग |
| ट्रांसफार्मरों की संख्या | 61 नग | 370 नग | 309 नग |
| 400 केवी ट्रांसफार्मर | 3 नग | 14 नग | 11 नग |
| 220 केवी ट्रांसफार्मर | 12 नग | 72 नग | 60 नग |
| 132 केवी ट्रांसफार्मर | 46 नग | 284 नग | 238 नग |
| ट्रांसफार्मरों की क्षमता | 3552 एमवीए | 27820 एमवीए | 24268 एमवीए |
| 400 / 220 केवी | 945 एमवीए | 4410 एमवीए | 3465 एमवीए |
| 220 / 132 केवी | 1350 एमवीए | 11280 एमवीए | 9930 एमवीए |
| 132 / 33 केवी | 1257 एमवीए | 12130 एमवीए | 10873 एमवीए |
| पारेषण लाइनों की लंबाई | 4845 सर्किट किमी | 14717 सर्किट किमी | 9872 सर्किट किमी |
| 400 केवी | 277 सर्किट किमी | 1938 सर्किट किमी | 1661 सर्किट किमी |
| 220 केवी | 1594 सर्किट किमी | 4383 सर्किट किमी | 2789 सर्किट किमी |
| 132 केवी | 2974 सर्किट किमी | 8395 सर्किट किमी | 5421 सर्किट किमी |

पारेषण अधोसंरचना के उन्नयन तथा विस्तार पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।



400 केवी डबल सर्किट लाइन



400 केवी डबल सर्किट टॉवर लाइन

(इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम) की मदद से माह सितम्बर-अक्टूबर 2024 में किया गया है। 1048.79 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। जिनमें 818.86 मेगावॉट के सोलर प्लांट सिंक्रोनाइज किए गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की केंद्रीय ग्रिड से पॉवर हस्तांतरण क्षमता वृद्धि हमारी भावी तैयारी का अहम सोपान है। 4 हजार 500 मेगावॉट क्षमता हासिल करना और 6 हजार की ओर बढ़ना भी हमारी प्रमुख उपलब्धि है।

## पारेषण-वितरण तंत्र का क्रमिक विकास

अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के जमाने में छत्तीसगढ़ की धरती का अति उच्चदाब क्षमता का पहला उपकेंद्र सन 1958 में भिलाई में स्थापित हुआ। 132 केवी क्षमता का दूसरा उपकेंद्र वर्ष 1959 में बिलासपुर में तथा इसी क्षमता का तीसरा उपकेंद्र वर्ष 1967 में भिलाई में स्थापित हुआ। वर्ष 2000 तक अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय तक 132 केवी उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 20 हो गई।

जहां तक 220 केवी और 400 केवी उपकेंद्रों का सवाल है तो यह जानना दिलचस्प होगा कि तीनों बड़ी क्षमताओं के प्रथम विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना भिलाई जिला दुर्ग में ही हुई। इसका प्रमुख कारण उस समय बिजली की सर्वाधिक मांग भिलाई इस्पात संयंत्र तथा इसके आसपास स्थापित सहायक उद्योगों में ही थी। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश के पहले बिजलीघर कोरबा

## पूँजी निवेश योजना में स्वीकृत व प्रस्तावित अति उच्चदाब उपकेन्द्र

| विवरण | निर्मित | निर्माणाधीन | निविदा प्रक्रिया में |
|---|---|---|---|
| 400/220 केवी उपकेन्द्र (2 नग) स्वीकृत | धरदेही | | पिथौरा |
| वर्ष 2025 – 2026 में (5 नग) प्रस्तावित | कुनकुरी जिला जशपुर, देवरी (बालोद) एवं कन्हेरा जिला रायपुर में 400 केवी जीआईएस उपकेन्द्र और आरंग जिला रायपुर एवं बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ में एआईएस उपकेन्द्र। जी.आई.एस. (गैस इंसुलेटेड प्रणाली) में केवल 132 केवी उपकेन्द्र रावणभाटा, रायपुर में संचालित है। | | |
| 220/132 केवी उपकेन्द्र (11 नग) स्वीकृत | पाटन, राजिम | दलदल सिवनी, सेमरिया, अहिवारा, कांकेर, धरमजयगढ़, एवं कुम्हारी | माल्दा (सारंगढ़), मुरेठी (परसतराई) एवं बचेली (किरंदुल) |
| वर्ष 2025 - 2026 में प्रस्तावित (11 नग) | गंडई, पिथौरा, मगरलोड, परसदा, झलप, कल्छा (जगदलपुर), नेवई-उतई, बरतोरी-तिल्दा, नंदोरखुर्द (सक्ती), हाफा, राजनांदगांव (सेकी-ढाबा) | | |
| 132 / 33 केवी उपकेन्द्र (32 नग) स्वीकृत | खैरागढ़, खरमोरा, सिलतरा फेस-दो इंदामारा, इंदागांव, माठ-खरोरा, छावनी, बैजलपुर, अमलेश्वर, टेमरी, आरंग, जनकपुर, मस्तूरी-मल्हार | मेटलपार्क केशकाल, बेतर, जामगॉव-आर, महराजपुर, बिलाईगढ़, अंडा, अर्जुनी, भिल्मी (बेलतरा) | सरोरा, उरला कॉलोनी, तरेकेला, चोटिया, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, जेवरा-सिरसा, सरगवा, सरायपाली, लखनपुर, रोहरा |
| वर्ष 2025 – 2026 में प्रस्तावित (19 नग) | नरहरपुर (कांकेर), बोडरीदादर (बागबाहरा), मडेली (छुरा), वटगन (पलारी), झिक्की (बगीचा), कुसमी, सहसपुर, फरसाबहार, असकला, सोनाडीह, अंतागढ़, जिल्दा, उफरा, कोडेनार, सोगरा, अभनपुर, कमलविहार, भान्सुला (अंबागढ़ चौकी), अरसमेटा (अकलतरा) | | |

- वर्ष 2025-26 हेतु पूंजी निवेश योजना का प्रस्ताव कुल 2433.41 करोड़ रुपये राशि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिन कार्यों की लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक है।


मल्टी सर्किट 220 केवी विद्युत पारेषण लाइन


132 केवी डबल सर्किट लाइन

से बिलासपुर होते हुए रायपुर और भिलाई की ओर बिजली प्रवाह का क्रम नहीं था बल्कि इसके उल्टे भिलाई में आने के पश्चात ही बिजली का ट्रांसमिशन रायपुर से बिलासपुर की ओर हुआ।

इस क्रम में यह उल्लेख करना उचित होगा कि जिस तरह 132 केवी का पहला उपकेंद्र वर्ष 1958 में भिलाई में स्थापित हुआ उसी तरह 220 केवी क्षमता का पहला उपकेंद्र भी भिलाई में वर्ष 1967 में और 400 केवी क्षमता पहला उपकेंद्र भी खेदामारा (भिलाई) में ही वर्ष 1983 में स्थापित हुआ। सुलभ संदर्भ के लिए विभिन्न उपकेंद्रों के स्थापना वर्षवार सूची प्रस्तुत है।

## 132 केवी उपकेंद्र

भिलाई (1958), बिलासपुर (1959), भिलाई (1967), किरंदुल (1968), रायगढ़ (1969), दल्ली राजहरा (1975), गुढ़ियारी (1976), महासमुंद (1976), चांपा (1977), विश्रामपुर (1977), जगदलपुर (1979), सिमगा (1980), दर्री (1981), राजनांदगांव (1982), बिरगांव (1983), धमतरी (1984), मनेंद्रगढ़ (1992), बलौदाबाजार (1996), पत्थलगांव (1996), रूआबांधा (2000), अंबिकापुर (2004), सारंगढ़ (2001), कवर्धा (2002), कचना (2002), कांकेर

# केंद्रीय क्षेत्र से पॉवर ड्रावल व राज्य की उपलब्ध पारेषण क्षमता वृद्धि

| पॉवरग्रिड (पीजीसीआईएल) द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्य | | |
|---|---|---|
| **विवरण** | **ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता व लाइनों की लंबाई** | **अनुमानित लागत** |
| धमधा रायपुर पूल एवं धरमजयगढ़ भैंसमा में विद्यमान 765/400 केवी उपकेन्द्रों में 400/220 केवी स्वीचयार्ड का निर्माण | 5 नग 500 एमवीए एवं 12 नग 220 केवी फीडर बे | 308 करोड़ |
| धमधा रायपुर पूल सें कुरूद धमतरी डबल सर्किट नई 400 केवी लाइनों का निर्माण कार्य एवं जैपुर पीजीसीआईएल उड़ीसा से जगदलपुर तक डबल सर्किट नई 400 केवी लाइनों का निर्माण | 90 कि.मी. (कार्य पूर्ण 22 मार्च 2025) 80 कि.मी. | 553 करोड़ |
| पॉवर ग्रिड के विद्यमान उपकेंद्र भाटापारा एवं रायगढ़ में अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना | 2 नग 500 एमवीए (कार्य पूर्ण) | 170 करोड़ |
| **सीएसपीटीसीएल द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्य** | | |
| 6 नग 400 केवी एवं संबंधित 400 केवी एवं 220 केवी लाइनों का निर्माण | 10 नग 500 एमवीए, 2 नग 315 एमवीए | 2981 करोड़ लगभग |

## छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 132 केवी गैस आधारित (जी.आई.एस.) उपकेन्द्र रावणभाटा (रायपुर) का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया। वर्ष 2025-26 की पूँजी निवेश योजना में 03 नग 400 केवी एवं 01 नग 132 केवी उपकेन्द्रों का गैस आधारित (जी.आई.एस.) तकनीक पर बनाया जाना प्रस्तावित है।

- छत्तीसगढ़ राज्य का पहला 132 केवी अंडरग्राउंड केबल 220 केवी. उपकेन्द्र डोमा एवं रावणभाटा (रायपुर) के मध्य वर्ष 2016 में संचालित किया गया।
- 220 केवी मल्टीसर्किट टॉवर लाइन (मोपका धरदेही-भाटापारा-सिलतरा) का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया है। अभी शहर के सघन जनसंख्या एवं सघन वन वाले इलाकों में मल्टी सर्किट टॉवरों का उपयोग लगभग सभी लाइनों पर किया जा रहा है।
- 14 नग 132 केवी लाइनों के पुराने कंडक्टरों (तारों) को उच्च क्षमता के एचटीएलएस कंडक्टरों से बदलने का कार्य किया गया है एवं 3 नग पारेषण लाइनों में कंडक्टर बदलने का कार्य प्रगति पर है।
- पहली बार 400 केवी रायता-कुरूद व रायता-जगदलपुर चालू लाइनों में रायपुर-विशाखापटटनम हाईवे के निर्माण हेतु टॉवर शिफ्टिंग व हाईट रेजिंग का कार्य ई.आर.एस. (इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम) की मदद से माह सितम्बर-अक्टूबर 2024 में किया गया है।
- सितम्बर 2025 की स्थिति में सीएसपीटीसीएल द्वारा 1048.74 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। जिनमें 815.86 मेगावॉट के सोलर प्लांट्स सिंक्रोनाइज किए गये हैं।

# छत्तीसगढ़ की पारेषण प्रणाली का तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

(2002), डोंगरगढ़ (2002), सक्ती (2003), राजिम (2003), बैकुंठपुर (2006), अकलतरा (2003), मुंगेली (2003), धमधा (2004), कुरूद (धमतरी) (2005), गुण्डरदेही (2005), बरमकेला (2006), नवागढ़ (2006), घरघोड़ा (2006), साजा (2009), तुलसी (2006), जशपुर (2006), डोंगरगांव (2007), झलप (2009), कुरूद (भिलाई) (2008), सिलपहरी (2008), खरसिया (2008), बागबहरा (2009), चकरभाठा (2011), बालोद (2010), पंडरिया (2010), माना (2010), भानुप्रतापपुर (2011), मंदिर हसौद (2012), कुहेरा (2012), उरला (2012), रसमड़ा (2012), बलरामपुर (2013), मगरलोड (2013), सरोना (रायपुर) (2013), सांकरा (2013), गंडई (2013), कोण्डागांव (2013), विश्रामपुर (2013), प्रतापपुर (2014), रतनपुर (2014), पथरिया (2014), गरियाबंद (2014), पुलगांव (दुर्ग) (2014), जैजैपुर (2015), कसडोल (2015), रेंकी (2016), कोनी (2016), रावणभाठा (2016), जगदलपुर (2017), चारामा

## कार्य क्रियान्वयन में

| क्र | योजना का नाम | विवरण | बजट प्रावधान | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अति उच्चदाब पारेषण लाइनों में जी.आई द्वारा अर्थ वायर को ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लयू) में बदलने का कार्य अनुमानित लागत रु. 178 करोड़ | आधुनिकतम संचार प्रणाली द्वारा अति उच्चदाब उपकेंद्रों एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र के माध्यम रियल टाइम डाटा ट्रांसफर हेतु सुचारू संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु। | 1. पी.एस.डी.एफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान राशि रु. 72.96 करोड़। 2. ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली राशि रु. 105.14 करोड़। | निर्धारित 5265 कि.मी. में से 5200 कि.मी. अर्थ वायर के स्थान पर ओपीजीडब्ल्यू बिछाने का कार्य पूर्ण तथा फोटे (फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल इक्विपमेंट) की स्थापना हेतु निविदा जारी। |
| 2 | SAMAST अनुमानित लागत रु. 18.68 करोड़ | डिमांड का वैज्ञानिक आकलन। उत्पादकों से पॉवर लेने की शेड्यूलिंग। इंटरफेस पाइंट्स पे लगे मीटर्स की ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। क्रेता/विक्रेता के बीच ट्रांसेक्शन सेटलमेंट। | 1. पी.एस.डी.एफ. योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान राशि - 13.14 करोड़। 2. ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली राशि रु. 5.54 करोड़। | 08 जनवरी 2025 को निविदा जारी। |
| 3. | Islanding scheme अनुमानित लागत रु. 17.41 करोड़ | राज्य के विद्युत ग्रिड में आपातकालीन स्थिति में रायपुर शहर स्थित विशेष उपभोक्ताओं जैसे अस्पताल, वीवीआईपी क्षेत्र, रेल्वे तथा हवाई अड्डा आदि को विद्युत प्रदाय करना। | 1. पी.एस.डी.एफ योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीकृत अनुदान राशि रु. 14.52 करोड़। 2. ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वहन की जाने वाली राशि रु. 2.89 करोड़। | एमओपी द्वारा 19 मार्च 2025 को रु. 14.52 करोड़ का अनुदान स्वीकृत। |
| 4. | HTLS अनुमानित लागत रु. 153 करोड़ | 132 केवी पारेषण लाइन में पैथर कंडक्टर को एचटीएलएस (हाई टैम्प्रेचर लो सैग) कंडक्टर से बदलना। | ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। | 31 मार्च 2025 को कार्यपूर्ण। |

## निकट भविष्य में प्रस्तावित कार्य

| क्र | योजना का नाम | विवरण | बजट प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 1 | STAMC अनुमानित लागत रु. 300 करोड़ | राज्य स्तर पर STAMC से 7 नग 220 केवी एवं 3 नग 400 केवी उपकेंद्रों का संचालन तथा शेष अति उच्चदाब उपकेंद्रों (1 नग 400 केवी, 20 नग 220 केवी एवं 100 नग 132 केवी) का संचालन एवं निगरानी का कार्य किया जाना प्रस्तावित। | ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा रु. 300 करोड़ वहन किया जाना प्रस्तावित। |
| 2. | प्रस्तावित 2x660 मेगावॉट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट, कोरबा वेस्ट से पॉवर निकासी हेतु प्लान। अनुमानित लागत रु. 475 करोड़ | प्रस्तावित पॉवर प्लांट से धरदेही तक 110 कि.मी. 400 केवी लाइन, 400 केवी कोरबा-खेदामारा लाइन को लीलो एवं 400 केवी कोरबा-रायता लीलो किया जाना प्रस्तावति। | टैरिफ बेस्ड कामपटेटिव बिडिंग (टीबीसीबी) के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित। |

(2018), सुकमा (2018), तखतपुर (2018), कोंडातराई (2018), डभरा (2018), मोहला (2018), बसना (2018), शिवरीनारायण (2018), भखारा (2018), लोरमी (2018), कोरबा (2003-04), बेरला (2018), बोरझरा (2007), बटोली (2018), कांसाबेल (2018), राजपुर (2018), वाड्रफ नगर (2018), नगरी (2018), पखांजूर (2018), दोरनापाल (2018), छुरी खुर्द (2018), नारायणपुर (2019), धरदेही (2019), बीजापुर (2020), उदयपुर (2021), खैरागढ़ (2022), इंदामारा (2022), खरमोरा (2022), इंदागांव (2023), मठखरोरा (2023), सिलतरा फेस-2 (2023), अमलेश्वर (2023), छावनी (2023), गुल्लू (आरंग) (2024), बैजलपुर (2024), टेमरी (बेमेतरा) (2024), मस्तूरी (बिलासपुर) (2025)। इनमें से कुछ उपकेंद्रों का उन्नयन कालांतर में 220 केवी उपकेंद्र के रूप में हुआ।

## 220 केवी उपकेंद्र

दुर्ग (1967), बारसूर (1980), भाटापारा 1984, उरला (1989), रायगढ़ (1997), मोपका (2002), सरायपाली (2014), कोटमीकला (2003), गुरूर (2004), सिलतरा (2006), बेमेतरा (2007), बनारी, (चांपा) (2007), महासमुंद (पारसवाणी) (2007), सुहेला (2008), राजनांदगांव (ठेलकाडीह) (2009), डोमा (रायपुर) (2010), पाटन (2024), रायता (रायपुर) (2013), विश्रामपुर (2013), छुरी (2014), मुंगेली (2014), गेरवानी (2016), जगदलपुर (2017), कवर्धा (2018), बोरझरा (2018), कुथरेल (धरसीवा) (2018), नारायणपुर (2019), धरदेही (2019), कुरूद (धमतरी) (2020), कोरबा (2021). इनमें से कुछ उपकेंद्रों का उन्नयन कालांतर में 400 केवी उपकेंद्र के रूप में हुआ।

## 400 केवी उपकेंद्र

खेदामारा (दुर्ग) (1983), रायता (रायपुर) (2013), जगदलपुर (2017), कुरूद (धमतरी) (2020), धरदेही (मुंगेली) 2025.

इस तरह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 400 / 220 केवी क्षमता के उपकेंद्रों की संख्या 5 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 3465 एमवीए है। 220/132 केवी क्षमता के उपकेंद्रों की संख्या 28 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 10960 एमवीए है। 132/33 केवी क्षमता के उपकेंद्रों की संख्या 103 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 12089.50 एमवीए है। इस प्रकार कुल अति उच्चदाब उपकेंद्रों की संख्या 135 तथा ट्रांसफॉर्मरों की कुल क्षमता 26514.50 एमवीए है।






C⚡PTCL
U.P.
VSTPS
Jharkhand
Madhya Pradesh
Orissa
Maharashtra
Andhra Pradesh
K.C.G.
Kanker
Kondagaon
Bastar
Sukuma
छत्तीसगढ़ की
पारेषण प्रणाली
LEGENDS

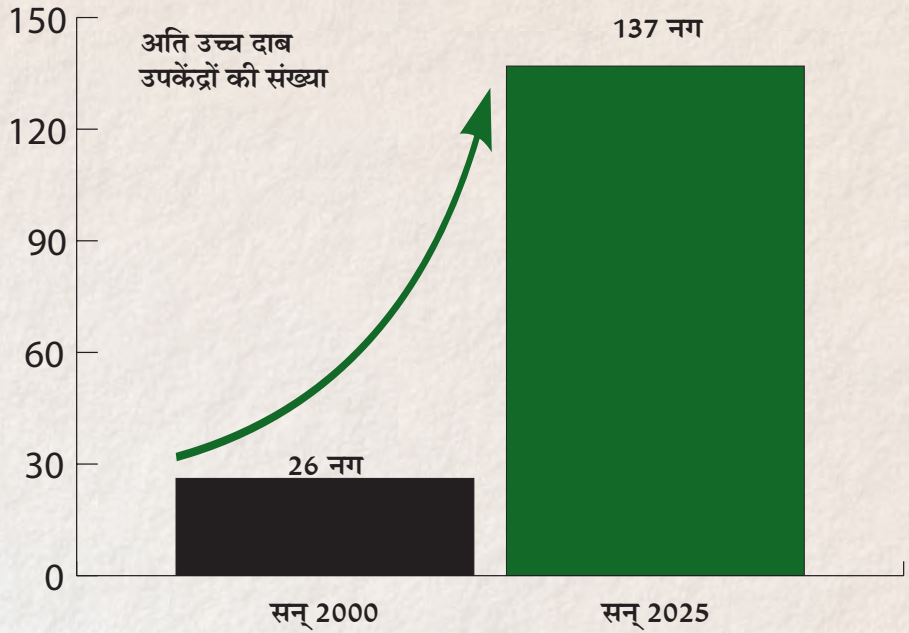
अति उच्च दाब
उपकेंद्रों की संख्या
137 नग
26 नग
150
120
90
60
30
0
सन् 2000
सन् 2025

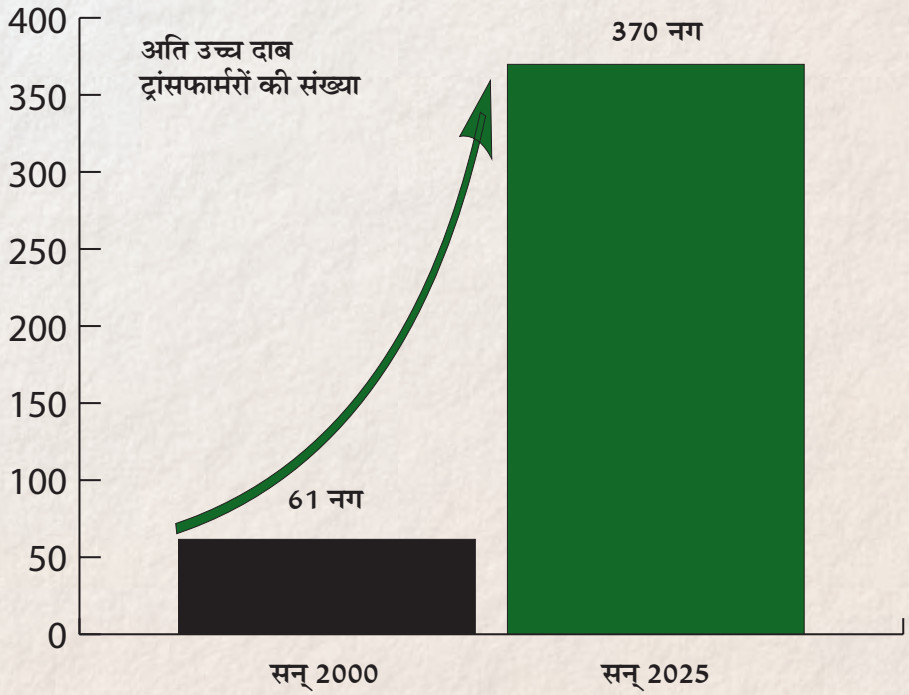
अति उच्च दाब
ट्रांसफार्मरों की संख्या
370 नग
61 नग
400
350
300
250
200
150
100
50
0
सन् 2000
सन् 2025

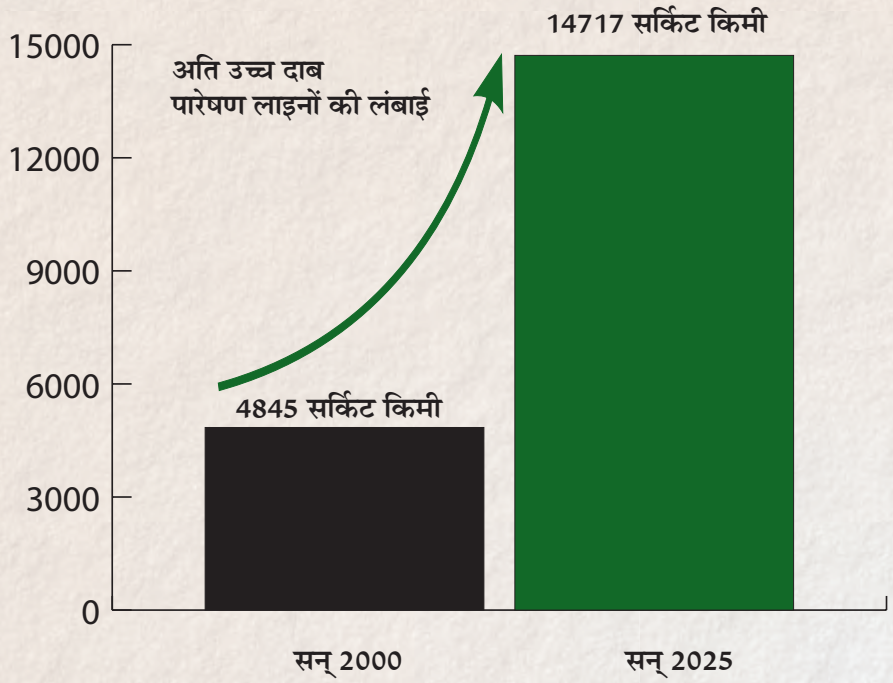
15000
12000
9000
6000
3000
0
अति उच्च दाब
पारेषण लाइनों की लंबाई
14717 सर्किट किमी
4845 सर्किट किमी
सन् 2000
सन् 2025

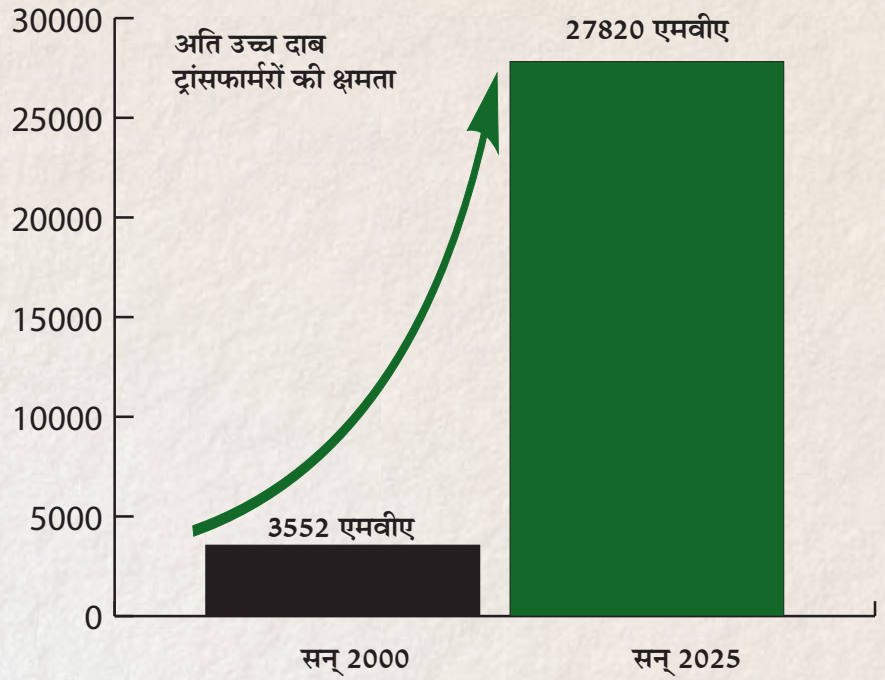
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
अति उच्च दाब
ट्रांसफार्मरों की क्षमता
27820 एमवीए
3552 एमवीए
सन् 2000
सन् 2025


पारेषण अधोसंरचना
संकल्प सिद्धि की ऊंची उड़ान

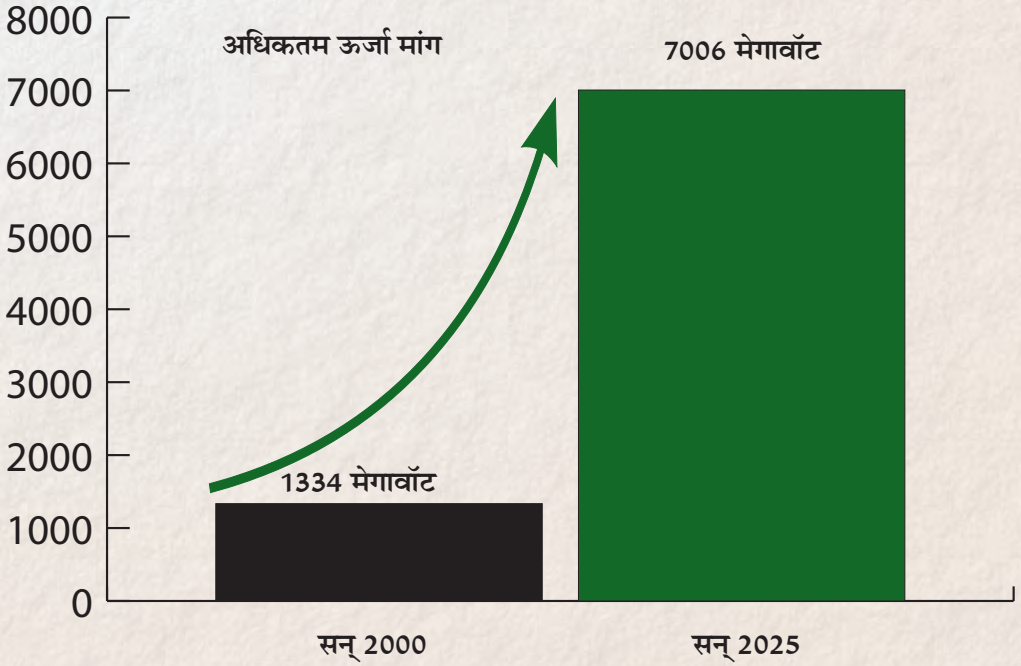
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
अधिकतम ऊर्जा मांग
7006 मेगावॉट
1334 मेगावॉट
सन् 2000
सन् 2025



छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में लगभग 19 लाख विद्युत उपभोक्ता थे जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 65 लाख से अधिक हो गई है। सिचाई पम्पों की संख्या लगभग 73 हजार थी जो अब बढ़कर 8.40 लाख हो गई है। उस समय बिजली की उच्चतम मांग 1334 मेगावॉट थी जो अब 7000 मेगावॉट को पार कर गई है। इन आँकडों से समझा जा सकता है कि वितरण प्रणाली में कितना विस्तार 25 वर्षों में हुआ है। इसी पैमाने पर उपभोक्ता सेवा और संतुष्टि के प्रयासों को देखना होगा कि हमने कितने बड़े लक्ष्य हासिल किये है और इसे बनाये रखने के साथ ही विस्तार की कितनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है।

▪ **डॉ. रोहित यादव** IAS
अध्यक्ष- सीएसपीजीसीएल / सीएसपीडीसीएल

# वितरण तंत्र - उपभोक्ता सेवा का मंत्र

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी उत्पादन तथा पारेषण कंपनियों के कार्यों को सार्थक बनाती है क्योंकि उपभोक्ताओं या जनता से सीधे सम्पर्क का माध्यम होती है। अंतिम रूप से कारखानों, व्यावसायिक संस्थानों, खेतों, शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाना इसी की जिम्मेदारी होती है। 25 वर्ष पहले अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन का बड़ा केंद्र तो था लेकिन छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता वाज़िब और पर्याप्त विद्युत प्राप्त करने से भी वंचित रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के उत्पादन का बड़ा हिस्सा अविभाजित मध्यप्रदेश के अन्य हिस्सों में चला जाता था। वास्तव में तब पूरे छत्तीसगढ़ में निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय के लिये समुचित वितरण अधोसंरचना का विकास ही नहीं हुआ था। राज्य गठन के बाद वितरण अधोसंरचना तथा उपभोक्ता सेवा के लिए किए गये प्रयास इसका उदाहरण हैं। विगत 25 वर्षों में अधोसंरचना विस्तार के क्रांतिकारी कदम उठाये गये है जिनके कारण 33 केवी लाइन की लंबाई 6,988 से बढ़कर 25,929 सर्किट किलोमीटर, 33 केवी उपकेन्द्रों की संख्या 248 से बढ़कर 1474, 33/11 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता 1,033 से बढ़कर 10,295 हो गई है। 11 केवी उपकेन्द्रों की संख्या 29,692 से बढ़कर 2,51,724 , इनकी क्षमता 1,951 से बढ़ कर 14,595 एमवीए, इनकी लंबाई 40,556 से बढ़कर 1,45,031 सर्किट किलोमीटर,

## वितरण अधोसंरचना - तब और अब

| विवरण | वर्ष 2000 | वर्ष 2025 | 25 वर्षों की उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| उपकेंद्रों की संख्या (नग) | 29,940 नग | 2,53,198 नग | 2,23,258 नग |
| 33/11 केवी उपकेंद्र | 248 नग | 1,474 नग | 1,226 नग |
| 11/04 केवी उपकेंद्र | 29,692 नग | 2,51,724 नग | 2,21,578 नग |
| उपकेंद्रों की क्षमता | 2,984 एमवीए | 24,800 एमवीए | 21,906 एमवीए |
| 33/11 केवी | 1,033 एमवीए | 10,295 एमवीए | 9,262 एमवीए |
| 11/04 केवी | 1951 एमवीए | 14,595 एमवीए | 12,644 एमवीए |
| वितरण लाइनों की लंबाई (सर्किट किमी) | 98,858 | 4,15,225 | 3,16,367 |
| 33 केवी | 6,988 सर्किट किमी | 25,929 सर्किट किमी | 18,941 सर्किट किमी |
| 11 केवी | 40,556 सर्किट किमी | 1,45,031 सर्किट किमी | 1,04,475 सर्किट किमी |
| निम्नदाब लाइन की लंबाई | 51,314 सर्किट किमी | 2,44,265 सर्किट किमी | 1,92,951 सर्किट किमी |
| उपभोक्ताओं की संख्या निम्नदाब | 18,90,998 | 65,31,180 | 46,40,182 |
| उपभोक्ताओं की संख्या उच्चदाब | 530 | 4,193 | 3,663 |
| विद्युतीकृत पंपों की संख्या (प्रावधिक) | 73,369 | 8,39,992 | 7,66,623 |
| ग्रामीण विद्युतीकरण संख्या | 17,071 | 19,609 | 2,538 मेगावॉट |
| विद्युतीकृत मजराटोलों की संख्या | 0 | 13500 | 13500 मेगावॉट |
| अधिक्तम मांग | 1334 | 7006 | 5669 मेगावॉट |




निम्नदाब लाइनों की लंबाई 51,314 से बढ़कर 2,44,265 सर्किट किलोमीटर हो गई है। निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या 18,90,998 से बढ़कर 65,31,180 तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं की संख्या 530 से बढ़कर 4,193 एवं विद्युतीकृत पम्पों की संख्या 73,369 से बढ़कर 8,39,992 हो गई है। इस वर्ष पीक डिमांड ने 7003 मेगावॉट को स्पर्श किया है जो सर्वकालिक उच्चतम स्तर हैं। यह लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति दिखा रहा है जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में तेजी का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में बिजली को आर्थिक रूप से कमजोर तबको की ताकत बनाने की पहल भी विकास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू होने के बरसों बाद भी देश में कई गांव विद्युतीकरण से वंचित थे। देश में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ''प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना'' (सौभाग्य) शुरू की थी। इस योजना के तहत वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ ने भी शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। छत्तीसगढ़ में बहुत सी बिरली बसाहटें हैं जो गांव की परिभाषा में नहीं आती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 17,000 बसाहटों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, 200 करोड़ रुपये लागत के कार्य प्रगति पर है। अब भारत सरकार ने शत-प्रतिशत घरों को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया है जिसके तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत प्रदेश की 7 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के 7160 से अधिक घरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 65 हजार 711 घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। नियद नेल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 68 ग्रामों के 5,725 घरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है व 43 गांवों में आवासों का काम प्रगति पर है। वितरण अधोसंरचना के विकास, उन्नयन एवं सुधार के लिए बड़े पैमाने पर कार्य चल रहे है। 33/11 केवी उपकेंद्र एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के 1100 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं। आर डी एस एस योजना अंतर्गत लाइन लॉस घटाने हेतु 3544 करोड़ रुपये के कार्यों में से लगभग 1800 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं। 27.58 लाख उपभोक्ता परिसरों में से 25 लाख परिसरो में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के सरगुजा संभाग के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र जनकपुर में रुपए 25 करोड़ रुपये की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र का निर्माण कर गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का कार्य पूरा किया गया है।



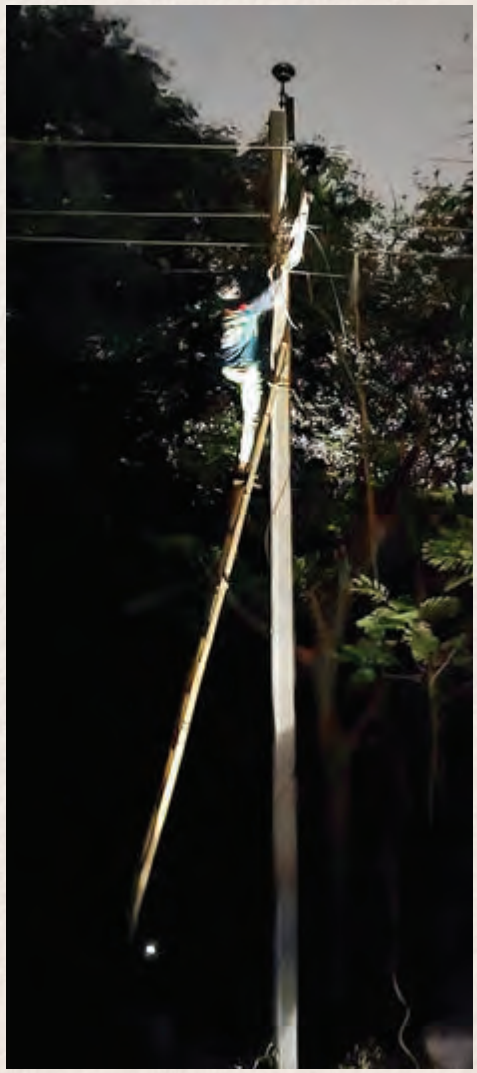



प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदेश की जनता को दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य की ओर से भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है जिससे प्रदेशवासी हॉफ बिजली बिल से निकल कर शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ सके। सस्ती बिजली के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहने के बजाय स्वयं बिजली के उत्पादक या ऊर्जादाता बन सके। फिलहाल तो दो वित्तीय वर्षों के लिए 1,35,000 रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है लेकिन राज्य सरकार 5,00,000 रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाने का बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पीएम कुसुम योजना भारत सरकार की वह अद्भुत पहल है जो किसानों और खेती को सौर ऊर्जा के फायदों से जोड़ती है। खेतों पर सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिये भारत सरकार आकर्षक सब्सिडी देती है। कुसुम-ए एवं बी विकेंद्रीकृत सोलर पॉवर प्लांट, ऑन ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिये है तथा कुसुम-सी ऑफ ग्रिड है। बंजर और अनुत्पादक भूमि व खेतों में सोलर प्लांट लगाने एवं ग्रिड से जुड़ाव होने से अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर भी किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है। किसान भाइयों की सर्वाधिक रूचि के कारण पीएम कुसुम-सी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 330 मेगावॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने का लक्ष्य मिला है। निविदा प्रक्रिया में राज्य को आशातीत सफलता मिली और 434 मेगावॉट के प्रस्ताव मिले। पूर्व लक्ष्य 330 मेगावॉट के एलओए जारी किये गये, जिनमें कार्य प्रारंभ हुआ और 7 मेगावॉट के प्लांट प्रचलन में आ भी चुके हैं। पूरी आशा है कि मार्च 2026 तक 330 मेगावॉट का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। कुसुम-बी के अंतर्गत 10 हजार कृषि पंपों के फीडर लेवल सोलराइजेशन का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया था। जिनकी क्षमता 44 मेगावॉट है। पी एम कुसुम-ए योजना अंतर्गत बस्तर संभाग के 20 नग 33/11 केवी उपकेंद्रों में 37 मेगावॉट एवं सरगुजा संभाग में 24 नग उपकेंद्रों में 44 मेगावॉट क्षमता के सोलर संयंत्रों हेतु अवार्ड जारी किए गए हैं। राज्य निर्माण से अभी तक औसत विद्युत की मांग में तीन गुने से अधिक की बढ़ोत्तरी के बावजूद छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश में लगातार विकास कार्य किये जा रहे।

## छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मैदानी उपस्थिति

| | | |
|---|---|---|
| क्षेत्रीय कार्यालय | 8 | रायपुर-शहर/ग्रामीण, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं रायगढ़ |
| वृत्त कार्यालय | 19 | 15 संचा. वृत्त एवं 04 शहर वृत्त |
| संभागीय कार्यालय | 68 | 55 संचा. संभाग एवं 13 शहर संभाग |
| उपसंभागीय कार्यालय | 159 | राज्य के विभिन्न शहरों एवं तहसील में |
| विद्युत वितरण केंद्र | 535 | राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में |
| जोन कार्यालय | 59 | राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में |

प्रदेश के उपभोक्ताओं एवं नये आवेदकों को विद्युत से संबंधित सेवाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिये वितरण कंपनी के निदेशक (संचा/संचा) (वाणिज्य एवं नियामक कार्य) के अधीनस्थ कार्यपालक निदेशक (संचा/संचा), मुख्य अभियंता (राजस्व) के साथ प्रदेश में वितरण केन्द्र, जोन, उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय कार्यरत है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 535 वितरण केन्द्र, 59 जोन, 159 उपसंभाग, 68 संभाग, 19 वृत्त, एवं 08 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य के सभी 535 वितरण केन्द्रों में वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा 535 वितरण केन्द्रों में से 320 वितरण केन्द्रों में दो पाली में 01 कुशल व 02 अकुशल श्रमिक व्यवधान को दूर करने एवं मरम्मत कार्य बाह्य स्त्रोत से कार्य नियोजित किये गये हैं एवं 215 वितरण केन्द्रों में 02 पाली में अतिरिक्त 01 कुशल एवं 02 अकुशल श्रमिकों के साथ 02 अतिरिक्त वाहन चालक भी उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार उक्त 215 वितरण केन्द्रों में यह व्यवस्था 03 पाली में उपलब्ध करायी गई है। इसी प्रकार 159 ग्रामीण उपसंभागों में कर्मचारियों की कमी के दृष्टिगत् 01 कुशल + 03 अकुशल श्रमिकों की गैंग एवं इसके अतिरिक्त 154 उपसंभागों हेतु अधिकतम 04 अकुशल श्रमिक कुल 616 अकुशल श्रमिक, नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य करने हेतु बाह्य स्त्रोत से नियोजित किये गये हैं। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर विद्युत सेवा उपलब्ध हो।

# वितरण अधोसंरचना विकास एवं विस्तार



## जीरो पॉवर कट

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त व निरंतर विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से हासिल की गई पहली उपलब्धि थी, 01 जनवरी 2008 को " जीरो पॉवर कट" राज्य घोषित किया जाना। इस तरह प्रदेश अघोषित विद्युत कटौती से मुक्त राज्य बनकर प्रदेश के विद्युत मानचित्र में अहम स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सहित 24x7 घण्टे बिजली प्रदाय की जाने लगी। वर्तमान में प्रदेश के 65 लाख 35 हजार 373 उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित ग्रामीण विद्युतीकरण के मापदण्डों के अनुरूप, प्रदेश के 19609 आबाद ग्रामों में से 18,728 ग्रामों को ग्रिड से विद्युतीकृत किया गया है एवं पहुचविहीन शेष 881 ग्रामों का विद्युतीकरण क्रेडा द्वारा ऑफ ग्रिड से किया गया। इस तरह वर्ष 2019 में प्रदेश के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।




## मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना

यह योजना वर्ष 2014-15 से संचालित है। जिसके तहत ऐसे आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों के मजरे-टोले बसाहटों का विद्युतीकरण किया जा रहा है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना के दायरे में नहीं आते। योजना प्रारंभ से अभी 591 करोड़ रु. के व्यय से लगभग 13 हजार 500 से अधिक मजरे-टोले के विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

## मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना (एसटीएन)

योजना की शुरूआत वर्ष 2021-22 में हुई। वर्ष 2023-24 हेतु 33/11 केवी क्षमता के 186 नये पॉवर सबस्टेशन, 225 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर, एवं 222 पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि, 3289 कि.मी 33 केवी लाइन, 2945 कि.मी 11 केवी लाइन के कार्यों की स्वीकृत, के विरूद्ध क्रमशः 147 नये पावर सबस्टेशन, 210 अतिरिक्त पॉवर सबस्टेशन, एवं 203 पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि के कार्य पूर्ण किए गए। 2045 कि.मी 33 केवी लाइन एवं 2296 कि.मी. 11 केवी लाइन निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु 33/11 केवी 102 (प्रथम चरण में 62 एवं द्वितीय चरण में 40) नये पावर सबस्टेशन स्थापना, 93 (प्रथम चरण में 80 एवं द्वितीय चरण में 13) अति. पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 246 (प्रथम चरण में 220 एवं द्वितीय चरण में 26) क्षमतावृद्धि के साथ-साथ 2271 कि.मी 33 केवी लाइन 1347 कि.मी 11 केवी लाइन के कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से क्रमशः 44 अति. पावर सबस्टेशन की स्थापना एवं 18 क्षमतावृद्धि के कार्यपूर्ण किए गए तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।



## मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना

यह योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 14 नगर निगम व नगरीय निकायों में विद्युत लाइनों का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाइनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना, तंग गलियों एवं व्यस्ततम मार्गों में सुरक्षा हेतु ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल करना, निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस योजना के तहत प्रदेश में 7 हजार से अधिक कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

## रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना लागू की गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों के लिये प्रभावी रहने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु अधोसंरचना में सुधार तथा विस्तार के कार्य प्रस्तावित हैं ताकि एक ओर जहां विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो वहीं दूसरी ओर लाइन लॉस में कमी आए। कृषि व अन्य उपभोक्ताओं के फीडरों को अलग किया जा सके जिससे विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि हो। अत्यधिक

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (R.D.S.S.) को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों के लिये लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ के लिये वितरण हानि में कमी के विभिन्न शीर्षों में कुल राशि 3544.38 करोड़ रू., स्मार्ट मीटरिंग हेतु कुल राशि 4089.97 करोड़ रू. की स्वीकृत प्रदान की गई है -

**री-मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजनांतर्गत लाइन लॉस में कमी -**

| क्र. | विवरण | इकाई | प्रावधान | कार्य पूर्ण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फील्डर पृथक्करण | | | |
| (i) | 11 के.वी लाइन | किमी | 12404.82 | 8818.57 |
| (ii) | डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर | नग | 14143 | 4400 |
| (iii) | एल.टी. लाइन | किमी | 4950.91 | 249.06 |
| (iv) | एल.टी. ए.बी केबल | किमी | 5703.23 | 1051.54 |
| 2 | 11 के की फीडर बाइफरकेशन | | | |
| (i) | 11 के.वी लाइन | किमी | 4471.93 | 2316.6 |
| 3 | एल.टी.ए.बी केबल कार्य | | | |
| (i) | एल.टी. ए.बी केबल (Reconductoring bare to AB Cable in theft prone area) | किमी | 22503.26 | 18825.61 |
| (ii) | एल.टी. ए.बी केबल (inter linking of LT Line for reduction of load area) | किमी | 9000.48 | 4533.61 |
| 4 | HVDS | | | |
| (i) | 11 के.वी लाइन | किमी | 1305.22 | 2.65 |
| (ii) | डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर | नग | 2371 | 642 |
| (iii) | एल.टी. ए.बी केबल | किमी | 2010.34 | 1462.71 |
| 5 | Replacement of Distribution Box by SMC box | नग | 50608 | 25673 |
| 6 | अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर | नग | 1105 | 588 |
| 7 | Armoured Cabling of Service lines | किमी | 2532.48 | 99.142 |







**स्मार्ट मीटर स्थापना की प्रगति (1 अक्टूबर, 2025 की स्थिति तक)**

| कार्य का विवरण | कुल स्वीकृत संख्या | स्थापना संख्या |
|---|---|---|
| 11 के.वी. फीडर मीटरिंग | 8315 | 5855 |
| वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग | 267001 | 51694 |
| उपभोक्ता परिसर में मीटरिंग | 7089902 | 2758306 |

विद्युत चोरी वाले क्षेत्रों में प्रोद्यौगिकी के माध्यम से रोकथाम की जा सके ताकि ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। स्मार्ट मीटरों के माध्यम से बिजली बिलों को सटीक बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य के लिये विद्युत हानि में कमी हेतु के लिए विभिन्न शीर्षों में कुल राशि 3544.38 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत, राज्यांश 10 प्रतिशत एवं ऋण 30 प्रतिशत है। स्मार्ट मीटरिंग हेतु कुल राशि 4089.97 करोड़ रु. की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें केन्द्रांश 15 प्रतिशत एवं कार्यदेशित एजेन्सी द्वारा 85 प्रतिशत का निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवीनीकरण कार्य हेतु 3939 करोड़ रू. का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

# हितग्राही मूलक योजनाएं



## कृषक जीवन ज्योति योजना

**कृषि पंपों को निःशुल्क/रियायती बिजली** – राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। इस छूट के अतिरिक्त कृषकों को फ्लैट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लैट रेट विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100 रुपये प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लैट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिंचाई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को 5 अश्वशक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए 200 रुपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए 200 रुपये अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रुपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। राज्य शासन को उक्त योजना के वर्तमान में प्रदेश के लगभग 8.39 लाख (5.87 स्थायी 2.52 अस्थायी पंप) से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है। वर्ष 2024-25 में सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राज्य शासन के बजट में 3500 रुपये करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। योजना प्रारंभ से अभी तक लगभग 27,000 रुपये करोड़ रु. की छूट पात्र कृषकों को दी जा चुकी है।



## सिंचाई पंप हेतु लाइन विस्तार

कृषि कार्य हेतु सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक विद्युत लाइनों के विस्तार के लिए दिशानिर्देश 1 सितंबर 2016 को जारी किए गए। तदनुसार किसानों को सिंचाई पंप कनेक्शन एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट तथा राज्य में नदी-नालों के किनारे पंपों के लिये आवश्यक विद्युत लाइन की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान की राशि प्रति पंप 75,000 रु. देय था, जिसे बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दिया गया। इस राशि में बचत होने पर 1,50,000 रूपये तक के लाइन विस्तार के कार्य करने का प्रावधान है। इस योजना से लाखों किसानों को सिंचाई पंपों हेतु बिजली कनेक्शन की सुविधा मिली है।

## बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह 30 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। योजना से प्रदेश के 15 लाख 17 हजार 975 बीपीएल उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

## मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA)

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के 42 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) की घोषणा 3 दिसंबर 2025 को की।



इस योजना में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। योजना का लाभ 01 दिसम्बर 2025 से होने वाली खपत पर दिया जाएगा।

साथ ही राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आगामी एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।

इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा।



पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल से फ्री बिजली बिल की ओर ले जाएगी।




# शहरों को अंडरग्राउंड केबलिंग की सौगात









शहरों को अंडरग्राउंड केबलिंग की सौगात छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में बिजली के बेतरतीब फैले तारों के कारण शहरों की सुंदरता प्रभावित होने लगी थी वहीं असुविधाएं भी बढ़ने लगी थीं। इस स्थिति से निजात दिलाने और सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना की शुरुआत अगस्त 2012 में की गई थी। इसके अलावा रायपुर तथा बिलासपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं भी संचालित की गई। नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवा रायपुर का विकास भूमिगत केबल की अवधारणा के साथ ही किया गया। रायपुर शहर में फाफाडीह से लेकर शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड होते हुए गांधी चौक, नगर निगम मुख्यालय कालीबाड़ी, बूढ़ापारा, बूढ़ा तालाब से लाखेनगर, आमापारा से टाटीबंध, सदरबाजार, गोलबाजार, बैजनाथपारा, रामसागर पारा, लाखेनगर से जीई रोड तक, राजेन्द्र नगर से डीडी नगर तक बहुत बड़े क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। जगदलपुर में बस्तर दशहरा रथ परिक्रमा मार्ग, दंतेश्वरी माई मंदिर क्षेत्र, गोलबाजार में अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है। बिलासपुर में पं. श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग, भक्त कंवर रामनगर क्षेत्र में कार्य पूरा किया गया है। अंबिकापुर में देवीगंज, सदर, ब्रह्मपारा क्षेत्रों में अंडरग्राउंड योजना केबलिंग की तैयारी की जा रही है। इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य शहरों में भी करने का प्रस्ताव है।

# दक्षता और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण संस्थान

अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले अभियंताओं से लेकर मैदानी अमले के लिए बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने, दक्षता और कौशल उन्नयन अतिआवश्यक होता है, इसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में तीन प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों में उत्पादन से लेकर पारेषण एवं वितरण कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें अभियंताओं को तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर लाइन परिचारक और कार्यालयीन कर्मचारियों की ट्रेनिंग शामिल है।

- **पीजीटीआई, कोरबा** – अविभाजित मध्यप्रदेश में कोरबा में विद्युत संयंत्रों के अभियंताओं और तकनीकी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1959 में की गई थी। 1976 में इसे पॉवर जनरेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (पीजीटीआई) के रूप में जाना जाने लगा। यहां उत्पादन कंपनी के अभियंताओं को नई तकनीक व नवाचारों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, रायपुर** – अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के समय केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के अधीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुढ़ियारी रायपुर में 8 जून 1989 से संचालित था। राज्य बनने के बाद निरंतर उन्नयन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में इसे केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसे वर्ष 2010 में मुख्य अभियंता (कार्यालय प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास) का दर्जा दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधीन यह संस्थान गुढ़ियारी स्थित सर्वसुविधायुक्त भवन में संचालित है। यहां कनिष्ठ अभियंता से कार्यालय सहायकों के कौशल विकास के लिए कार्य किया जाता है। उनके लिए 75 दिन तक के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। यहां कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक एवं लाइनमैन के साथ-साथ लेखा प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता का विस्तार भी किया जाता है। कर्मचारियों को सूचना के अधिकार के साथ-साथ विद्युत सुरक्षा एवं सतर्कता संबंधी जानकारी के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।
- **प्रशिक्षण केंद्र अंबिकापुर** – इसके अलावा अंबिकापुर में प्रशिक्षण केंद्र 5 सितंबर 1989 से संचालित है, जहां लाइन कर्मचारियो (परिचारक श्रेणी एफ/डी/टी-लाइनमैन) को विद्युत लाइनों के निर्माण एवं उनके रखरखाव सहित सुरक्षित कार्य संपादन का लिखित व प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मैदानी अमले को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ विद्युत सुरक्षा, सतर्कता एवं रखरखाव के लिए दक्ष किया जाता है।










# नक्सलवादी हमलों से कई बार बस्तर में ब्लैक आउट...

## सुधार के दौरान हमले से विद्युत कर्मियों की शहादत, आपदा से सबक और निर्धारित समय में दोहरी लाइन का निर्माण

24 फरवरी, 2006, बोदली/23 मार्च, 2006 धनोरा/31 मई, 2007 झाराघाटी नारायणपुर/ 5 जून, 2008 बारसूर-भिलाई लाइन। ये तारीखें बस्तर में नक्सलवादी हिंसा और क्रूरता से बिजली आपूर्ति ठप्प किये जाने का इतिहास बताती है। ये हमला वास्तव में भिलाई से बारसूर के बीच 220 केवी अतिउच्चदाब की 238 किलोमीटर की लाइन तथा दर्जनों टॉवरों को ध्वस्त करते हुए जनजीवन को त्रस्त करने की दुर्भावना से ग्रसित था।

ध्वस्त टॉवरों और लाइनों के सुधार हेतु जब बिजली विभाग का अमला पहुंचता था तब घने जंगलों में उनके वाहनों पर भी नक्सली हमले होते रहें, जिसके कारण तीन विद्युत कर्मी शहीद हुए। कापसी और मर्दापाल के बीच सबसे बड़ी घटना में न सिर्फ विद्युत कर्मी हताहत हुए बल्कि बड़ी संख्या में एस.टी.एफ के जवान भी हताहत हुए। 31 मई का हमला तो इतना भयंकर था कि उसके बाद राज्य सरकार ने सार्वजनिक आपदा की घोषणा की। मंत्रालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, विद्युत मण्डल अध्यक्ष सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। उच्चस्तरीय मानीटरिंग का इंतजाम किया गया। इस


बस्तर में फिर अंधेरा
नक्सली करतूत, उड़ाए चार बिजली टावर
सप्ताह भर में दूर होगा अंधकार
मुख्यमंत्री ने की समीक्षा


ठहर गया बस्तर


नक्सली विस्फोट में तीन विद्युत कर्मियों की मौत


दक्षिण बस्तर में दूसरे दिन भी अंधेरा


देशबन्धु
विद्युत संकट: सार्वजनिक आपदा की घोषणा


बस्तर विद्युत लाइन विस्तार के लिए पचास करोड़ मंजूर


'नक्सली हिंसा शर्मनाक'

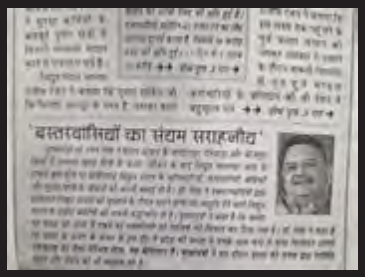
बस्तरवासियों का संयम सराहनीय


नक्सलियों ने विद्युत सुधार दल को खदेड़

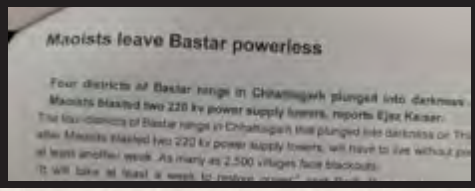
Maoists leave Bastar powerless

अखबार संदर्भ
देशबंधु लाइब्रेरी

# बिजलीकर्मियों के बलिदान, शौर्य और समर्पण की गाथा...

## हमेशा के लिए अंधेरा दूर करने के दूरगामी इंतजाम, 400 केवी अधोसंरचना तैयार

दौरान दो वर्षों में नक्सलियों ने न सिर्फ 220 के.वी. के तीन टॉवर उड़ाये बल्कि अनेक छोटे-बड़े टॉवरों, लाइनों को बम विष्फोट से ध्वस्त करते रहे। जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ और बॉक्साइट, आयरन ओर, खदानों का काम, रेलवे द्वारा टेनों का संचालन आदि कार्य भी प्रभावित हुए। शासन तथा विद्युत मण्डल के दृढ़ संकल्प और अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार काम करने की जिद से बार-बार ध्वस्त विद्युत आपूर्ति को पुनः चालू किया गया। उसी दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि 160 किलोमीटर डबल सर्किट लाइन का निर्माण किया जाये। जिसे बाद में 400 केवी अधोसंरचना में तब्दील किया गया। 50 करोड़ की लागत से कांकेर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के समानान्तर उच्च दाब लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी गई। आपदाकाल में आंध्रप्रदेश के मरियागुड़ा से कोंटा लाइन के द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई। बड़ी संख्या में जनरेटर की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी आपदा के पूर्ण समाधान में 11 दिन लगे। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने दिन-रात एक करके सुधार कार्य किया। नक्सलियों द्वारा किये गये विध्वंस के सुधार में विद्युत कर्मियों के समर्पण को देखते हुए इस कार्य में लगे करीब 200 लोगों का सम्मान मुख्यमंत्री निवास में किया गया था।

घटना की भयावहता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सुधार कार्य सुरक्षा बलों की निगरानी में किया गया।




बिजली और सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों ने हमले किए । कर्मवीरों का हौसला बढ़ाने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह झाराघाटी पहुंचे थे। उस समय प्रमुख सचिव (ऊर्जा) श्री विवेक ढांड, ऊर्जा सलाहकार श्री शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव (ऊर्जा) श्री अमन कुमार सिंह, डीजीपी श्री संतकुमार पासवान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष श्री राजीब रंजन, सदस्य (पारेषण एवं वितरण) श्री पीके जैन एवं श्री मनोज कुमार डे, सलाहकार ऊर्जा विभाग श्री एपी नामदेव के सतत् निर्देशन में यह कार्य चला।

जिसमें मुख्य अभियंता श्री डीपी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री शंकर डे, अधीक्षण अभियंता श्री विजय सिंह, श्री पीके चौधरी, कार्यपालन अभियंता श्री पीके गुप्ता, सहायक अभियंता श्री पीवी शंकर सहित 200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की टीम ने सीआरपीएफ नागा बटालियन जवानों की सुरक्षा में दुर्गम और घने जंगलों के बीच कैंप करके टॉवर को पुनः खड़ा किया। इस दौरान तीन बार नक्सली हमले भी हुए, जिसमें एक घटना में सहायक लाइनमेन श्री चेतन लाल कामड़े कोंडागांव, वाहन चालक श्री नियाज अहमद अंसारी एवं विद्युत ठेकेदार श्री सुशील भद्र शहीद हो गए थे। दूसरी घटना में नागा बटालियन का एक सिपाही शहीद हो गया। एक अन्य घटना में सीआरपीएफ की नागा बटालियन एवं मिजो बटालियन ने पुल पर एंबुश लगाते हुए नक्सलियों पर फायरिंग की, जिसमें एक नक्सली मारा गया।


आजादी के 75 साल बाद छिन्दौला पहुंची बिजली


सुकड़ीअुहान के 10 परिवारों को आजादी के बाद पहली बार मिली बिजली की सुविधा, जनजाति केंद्र सरकार का आभार, घरों में विद्युत विभाग ने लगाए निशुल्क विद्युत कनेक्शन


बिजलीविहीन विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपनी


सुविधा और विकास : ग्रामीणों को लालटेन से छुटकारा पाने में लग गए 7 दशक

लूठापारा गांव की कमार बस्ती तक 75 साल बाद बिजली पहुंची तो झूमे लोग


अब तक बिजलीविहीन विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य महुआपना म


बीजापुर के सुदूर वनांचल में सुशासन का सूर्योदय, तिमेनार में पहली बार पहुंची बिजली


पालनार के 300 से अधिक घरों में हुआ उजियारा


धुर नक्सल प्रभावित गांव मुदवेंडी में पहुंची बिजली


नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत पुसकोंटा के ग्रामीणों को मिली बिजली और पानी की सौगात

## प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ राज्य के लिए 07 पीवीटीजी जनजाति यथा अबूझमाडिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरवा, कमार, शहरिया एवं बीरहोर जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम जन-मन योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत् राज्य में 18 जिलों की जनजातियों के 7160 आवासो को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जा चुका है। केवल सरगुजा जिले के 123 आवासों का कार्य पहुंच विहीन मार्ग होने के कारण शेष है।

## धरतीआबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं छूटे हुए आवासों के विद्युतीकरण हेतु प्रदेश के 28 जिले के 6863 बसाहटों के 65,711 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने के लिए राशि 324 करोड़ रू. की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में उक्त जिले के कार्य को पूर्ण करने हेतु 13 पैकेज में ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। विद्युत खंभे खड़े करने का कार्य प्रगति पर है।





## बस्तर पहुंचे ऊर्जा सचिव डॉ.रोहित यादव, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश...

छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा सचिव तथा उत्पादन व विद्युत कंपनियों के अध्यक्ष डॉ रोहित यादव ने 24-25 मई को बस्तर संभाग क्षेत्रीय मुख्यालय जगदलपुर का दौरा किया उनके साथ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंपनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। डॉ यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना तथा मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना से आदिवासी अंचलों को तेजी से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सुकमा जिले के जगरगुंडा तथा बीजापुर जिले के भद्रकाली व गंगालूर उपकेन्द्रों 132/33 केवी उपकेन्द्र जामगांव का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। विद्युतपुरा में 33/11 केवी उपकेन्द्र के लिये प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। जगदलपुर में स्टॉक काउंटर खोलने का प्रस्ताव भेजने व संचालन- संधारण कार्यों में विशेष ध्यान देने को कहा। हर घर में बिजली पहुंचाने वाली केंद्रीय योजनाओं तथा क्षेत्रीय विकास के लिए अन्य योजनाओं के साथ ही नियद नेल्लानार योजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी डॉ यादव ने दिये।

विद्युत कंपनी के एमडी पहुंचे सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूवर्ती

## खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू



## दशकों बाद पैदागेल्लुर हुआ रोशन, नियद नेल्लानार योजना से गांव में पहुंची बिजली





## आदिवासी अंचलों और घरों में बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज

# 77 years post Independence, three CG villages illuminated

### Electric Poles Earlier Installed In 1997; Long Wait Brings Light

Rashmi.Dolia
@timesofindia.com

Raipur: After a long wait of 77 years since independence, it's for the first time that the three villages of Koriya district have finally been illuminated with electricity supply. It took 50 years after independence to install electric poles in the region, but they didn't work. New poles have been set up recently for power supply.

"It's for the first time that I am able to study late till night sitting at my home under an electric lamp and am happy that my family can buy a fan this summer as we have power supply reaching





roach road either. But people's will and community support ignited the will to do it. Next target is to get them 4G BSNL mobile network."

She informed that Chhattisgarh State Electricity Distribution Company took up the task of lighting up these villages under Chief Minister Majratola Electrification Scheme. In Tarra village, 12 km of 11 KV and nine km of LT lines were laid at a cost of Rs 55 lakh, and three transformers were installed, providing electricity to 88 homes, and similar with other Mendra and Baser too.

Collector Tripathi said that efforts are ongoing to extend electricity to the re-

## अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी, आजादी के बाद टेकलगुड़ियम में पहुंची बिजली







## नियद नेल्लानार योजना

इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के समीप 5 कि.मी. परिधि में आने वाले ग्रामों का ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण करने का कार्य किया जाना है। जिसके तहत् वर्तमान में चिन्हांकित 56 कैम्प के अंतर्गत 171 ग्रामों के 13862 हाउसहोल्ड के विरूद्ध 37 कैम्पों के अंतर्गत 68 ग्रामों के 5725 घरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले 180 ग्रामों का ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु सर्वे कार्य प्रक्रियाधीन है।

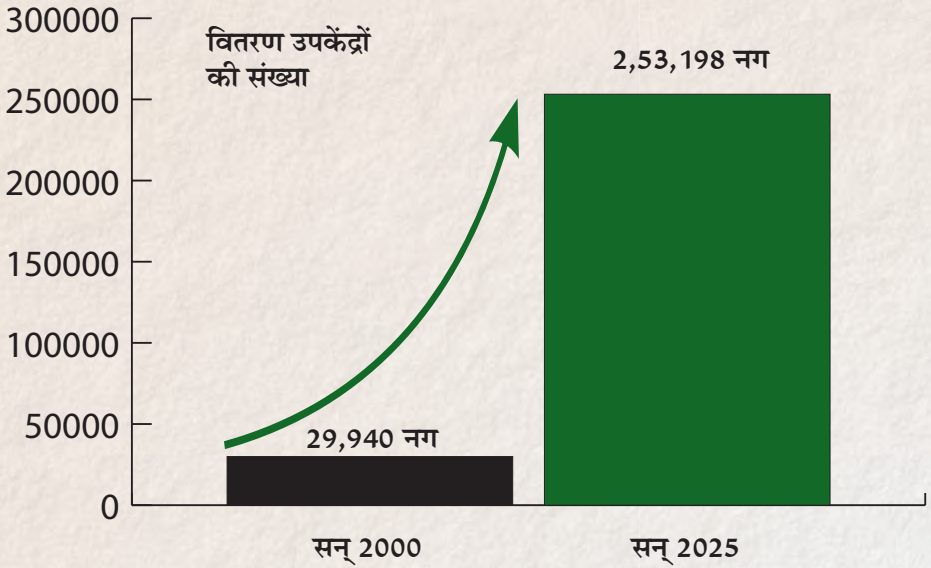
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
वितरण उपकेंद्रों
की संख्या
2,53,198 नग
29,940 नग
सन् 2000
सन् 2025

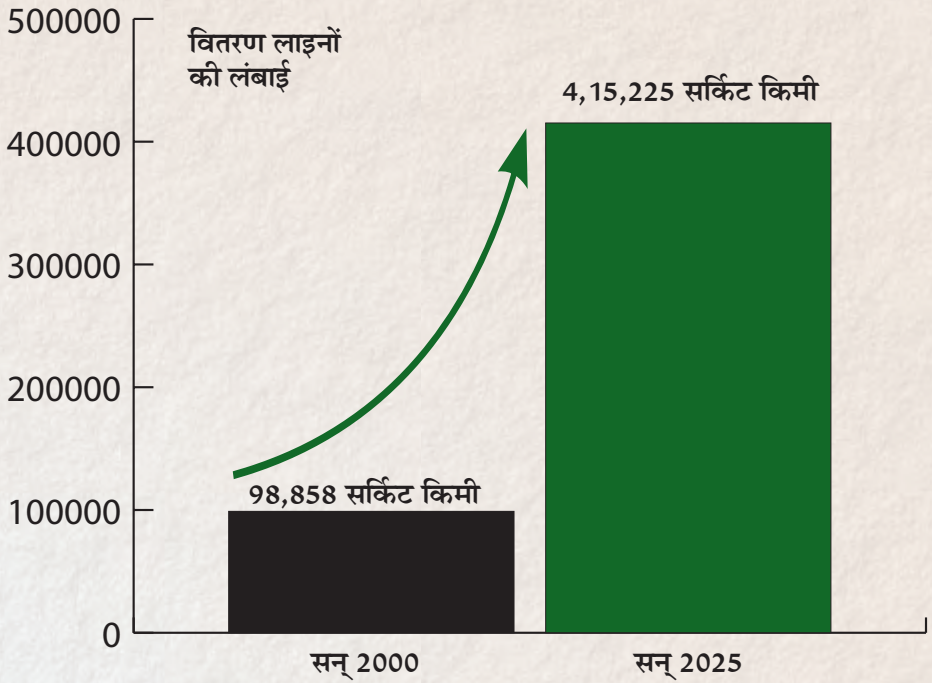
500000
400000
300000
200000
100000
0
वितरण लाइनों
की लंबाई
4,15,225 सर्किट किमी
98,858 सर्किट किमी
सन् 2000
सन् 2025

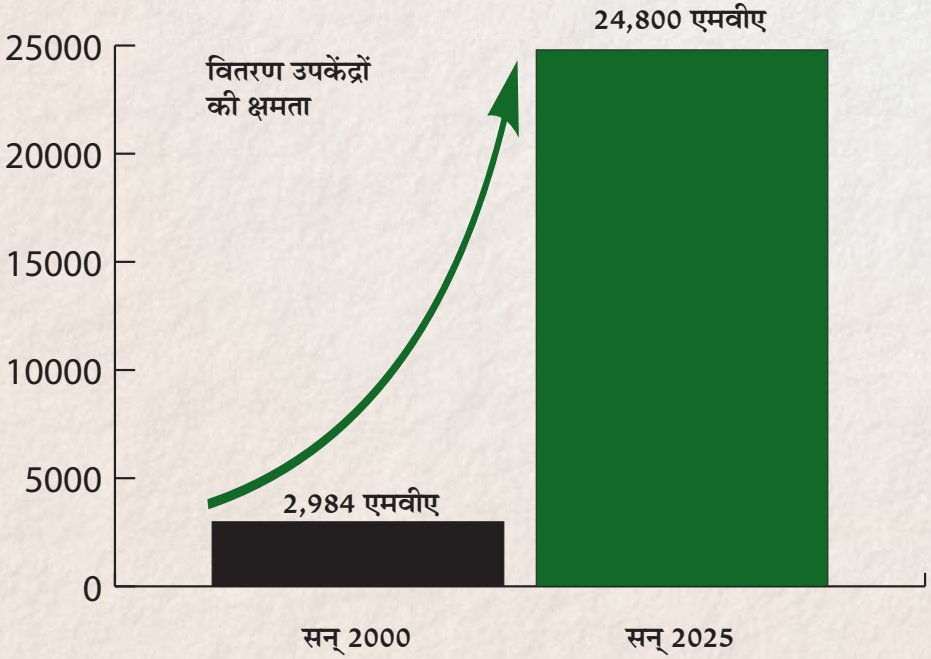
25000
20000
15000
10000
5000
0
वितरण उपकेंद्रों
की क्षमता
24,800 एमवीए
2,984 एमवीए
सन् 2000
सन् 2025

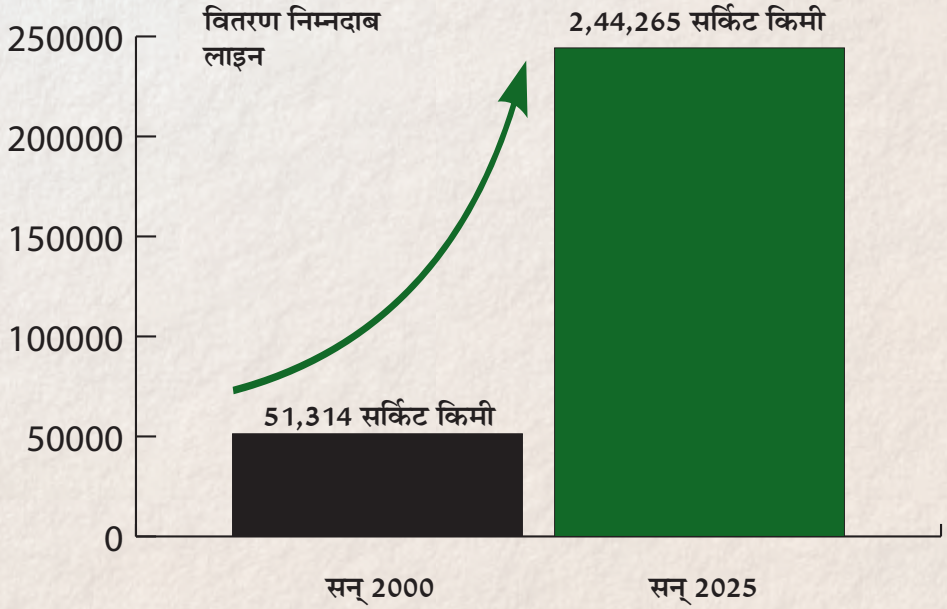
250000
200000
150000
100000
50000
0
वितरण निम्नदाब
लाइन
2,44,265 सर्किट किमी
51,314 सर्किट किमी
सन् 2000
सन् 2025

# वितरण अधोसंरचना संकल्प सिद्धि की ऊंची उड़ान



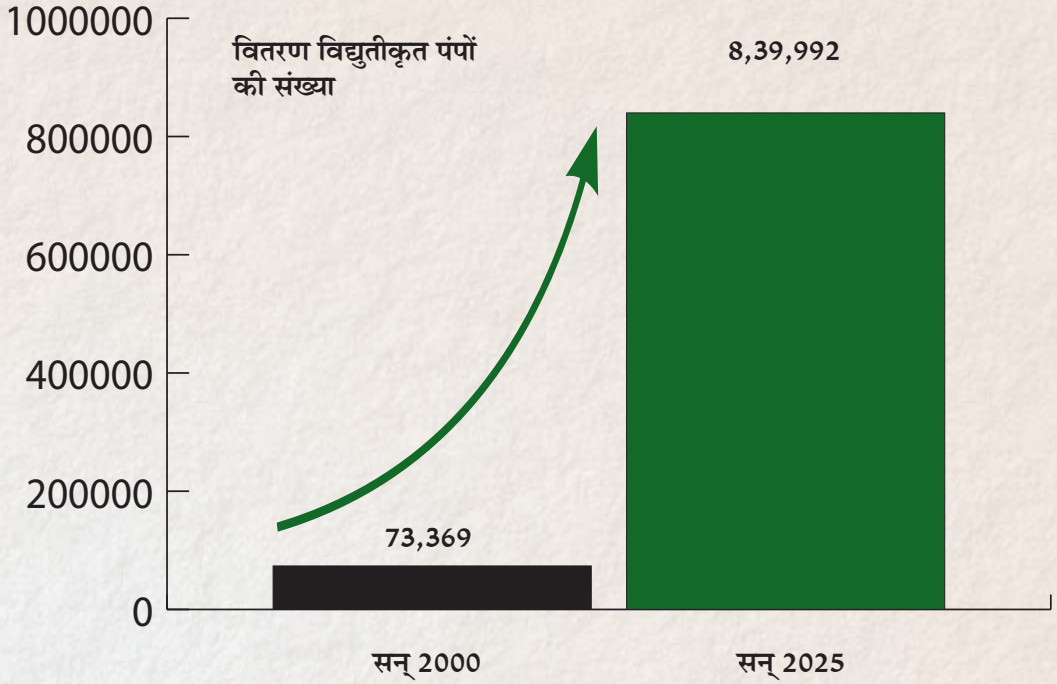


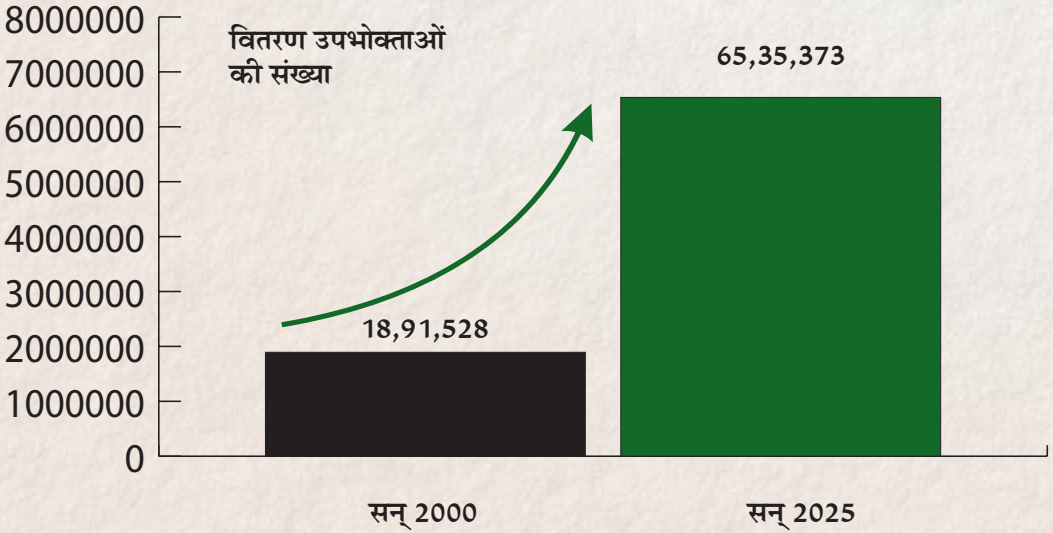


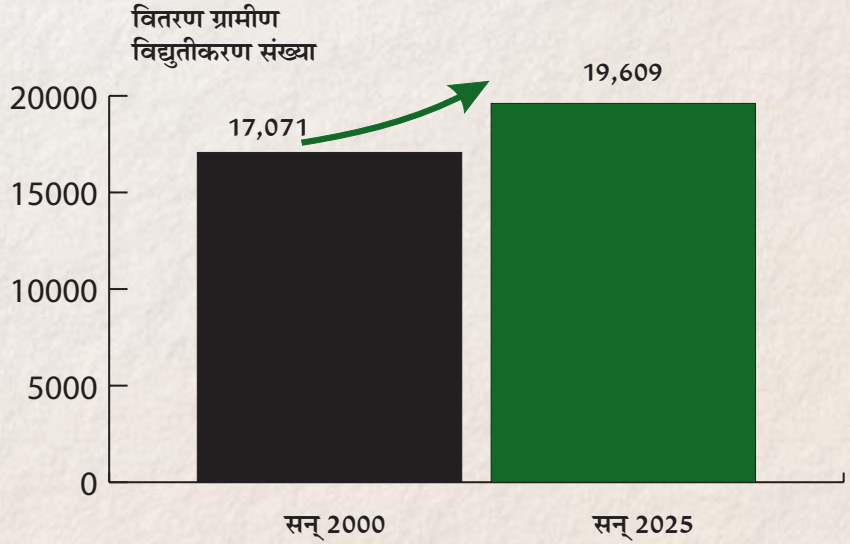




सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह

# प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

1 से 3 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र अपने घरों पर स्थापित करने के लिए घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत देश में 1 करोड़ व प्रदेश में 1 लाख 30 हजार घरों में प्रारंभिक तौर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान राज्य सरकार द्वारा भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है ताकि प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल प्रदाय से आगे बढ़कर निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सके। 1 से 3 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। राशि 78,000 रू. केन्द्र सरकार एवं 30,000 रू. राज्य सरकार अनुदान दे रही है। उपभोक्ता अपनी



सभी जिलों के लिए सूर्यरथ की रवानगी

आवश्यकतानुसार इससे अधिक क्षमता का भी संयंत्र स्थापित कर सकता है पर अनुदान सिर्फ 3 किलोवाट तक ही देय है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 01 लाख घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत 11 हजार घरो की छतों पर सोलर संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है एवं लगभग 1,00,000 सोलर संयंत्र स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

## पीएम कुसुम योजना

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना के कम्पोनेंट-ए के तहत् वितरण कंपनियों में स्थापित 33/11 केवी सबस्टेशनों के 05 कि.मी. की परिधि में अनुपजाऊ कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावॉट तक विकेन्द्रित भूमिकृत ग्रिड कनेक्टेड सोलर अथवा अन्य नवकरणीय ऊर्जा आधारित स्त्रोतों के संयंत्रों की स्थापना की जानी है। इस हेतु पूर्व में 14.5 मेगावॉट के आबंटन प्राप्त हुए थे, जिसके विरूद्ध 9 नग 7 मेगावॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट संचालित हैं। वर्तमान में पुनः 300 मेगावॉट का आबंटन छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध अवॉर्ड जारी किया जा चुका है।

कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत 7.5 एच.पी. तक के ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों को विद्युत प्रदान कर रहे 11 केवी फीडरों के सोलराईजेशन के कार्य शामिल है। जिसके तहत् कृषि पंप के स्थापित क्षमता के दुगनी क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ को 10,000 पंपो के सोलराईजेशन के लिए आबंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 8903 पंपो हेतु 38 मेगावॉट का अवॉर्ड जारी किया जा चुका है शेष 1100 पंपो का अवॉर्ड जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

# देश का प्रथम सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

## सोलर पार्क (सेकी)

राजनांदगांव क्षेत्र में सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावॉट क्षमता सह 40 मेगावॉट/120 MWh (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सहयोग से की गई है। परियोजना की स्थापना 1 फरवरी 2024 को हुई थी एवं इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2024 को किया गया था। यह देश का प्रथम सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

इसके लिए बंजर भूमि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उपलब्ध कराई गई थी, जिसे त्रिपक्षीय भूमि उपयोग अनुमति समझौते के तहत SECI को सौंप दिया गया। यह परियोजना 9 गाँवों में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल 182.29 हेक्टेयर है। यहां पॉवर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार प्रति वर्ष 243 मिलियन यूनिट (24.3 करोड़ यूनिट) बिजली उत्पादित होती है। हालांकि 120 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम केवल 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में केंद्रित है। यहां उत्पादित बिजली 132 केवी डबल सर्किट 28.6 कि.मी. ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 132/220 केवी ठेलकाडीह उपकेंद्र तक पहुंचाई जाती है। सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने और भण्डारण के लिए फोटोवोल्टेयिक सेल का उपयोग किया जाता है। यहां उत्पादित अतिरिक्त बिजली जो भण्डारण नही हो पाती उसे ग्रिड में भेजा जा सकता है। गैर-सौर घंटों में, यह परियोजना लगातार 3 घंटे तक 40 मेगावॉट की गारंटीकृत बिजली आपूर्ति प्रदान करती है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र में 25 वर्षों में लगभग 29 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम होगी। यह मात्रा लगभग 13.18 करोड़ पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन के बराबर है।













# उपभोक्ता-सेवाएं और सुविधाएं

## मोर बिजली मोबाइल ऐप

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए मोर बिजली एन्ड्राइड मोबाइल ऐप सुविधा प्रारंभ की है। यह मोबाइल ऐप "मोर बिजली ऐप" के नाम से गूगल प्ले-स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है, "मोर बिजली" लिखकर सर्च करके इंस्टॉल किया जा सकता है। इस ऐप में बिल संबंधित सुविधाएँ जैसे नवीनतम मासिक बिजली बिल, बिजली बिल की गणना, नवीनतम टैरिफ (बिजली की दरें), पिछले 24 माह के बिजली खपत पैटर्न देखने की सुविधा आदि उपलब्ध है। इसमें बिल भुगतान संबंधी जैसे ऑनलाइन भुगतान, क्यू. आर. कोड स्कैनर, नजदीकी भुगतान केन्द्र, पिछले 24 माह के बिल भुगतान का विवरण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस ऐप में बिजली संबंधी शिकायतों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे परिसर में बिजली बंद होने की शिकायत, बिजली बिल संबंधित शिकायत, आपातकालीन शिकायत, उपभोक्ता के परिसर वाले क्षेत्र से संबंधित विद्युत अवरोध की जानकारी, ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसी प्रकार विभिन्न तरह के आवेदन जैसे नये बिजली कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन, नाम परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन, टैरिफ परिवर्तन हेतु ऑनलाइन आवेदन, लोड बढ़ाने-घटाने हेतु ऑनलाइन आवेदन, मीटर शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन, उपभोक्ता के द्वारा दर्ज ऑनलाइन आवेदन की स्थिति आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार मीटर रीडिंग हेतु विद्युतकर्मी को बुलवाने, उपभोक्ता की व्यक्तिगत प्रोफाइल में परिवर्तन की सुविधाएं जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलें, दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें, ईमेल आई.डी. जोड़ें की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिजली कनेक्शन प्रोफाइल के लिए बिजली कनेक्शन की जानकारी, बिजली नेटवर्क की जानकारी, बिजली ऑफिस की जानकारी आदि सुविधाएं ऐप में उपलब्ध हैं।





## केंद्रीयकृत विद्युत कॉल सेंटर- 1912

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायपुर में केंद्रीयकृत कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। जहां 24×7 आधार पर टोल-फ्री फोन नं. 1912 डायल कर विद्युत उपभोक्ता अपनी शिकायतें व समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इस कॉल सेंटर से उपभोक्ता अब पूर्व में दर्ज लंबित शिकायत की स्थिति की जानकारी, विद्युत बिल भुगतान से संबंधित जानकारी

वितरण कंपनी की विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां हिन्दी-छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी भाषा एस.एम.एस. तथा ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने, शिकायत के पंजीयन, उसके निराकरण के बाद उपभोक्ता को एस.एम.एस. द्वारा सूचना देने की सुविधा भी है।

## ई-संपर्क सेवा

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड कराने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारियाँ निःशुल्क भेजी जाती हैं। मासिक विद्युत बिल, बिल का भुगतान, बिल भुगतान की नियत तिथि से तीन दिन पहले स्मरण सूचना, कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराने पर सूचना, शिकायत का निराकरण होने पर सूचना दी जाती है।

## विद्युत बिल के भुगतान हेतु सुविधाएँ

वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग (47 अधिकृत बैंक) के माध्यम से विद्युत बिल के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। जिसके अंतर्गत भारत बिल पेमेंट सर्विस, पे-टी.एम मोबाईल एप तथा पे-टी.एम वेबसाइट, एयरटेल मनी, वोडाफोन एम-पैसा, एम-रूपी, ऑक्सीकैश, फ्री-चार्ज तथा जिओ मनी आदि के माध्यम से विद्युत बिल के भुगतान की सुविधा दी गई है। इसके अलावा विद्युत कंपनी कार्यालयों में 131 ए.टी.पी. मशीन के माध्यम से सप्ताह के सातों दिन प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक विद्युत बिल के भुगतान की सुविधा दी गई है। 9100 कॉमन सर्विस सेन्टर, 1700 पे. पाईंट सेंटर के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

## ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएँ

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएँ इस प्रकार हैं- बिजली बिल से संबंधित ऑनलाइन सुविधाएँ- नवीनतम बिल की जानकारी, ऑनलाइन भुगतान, भुगतान की रसीद प्रिंट, वर्तमान तथा पिछले 11 माह के डुप्लीकेट बिल प्रिंट, पिछले 24 माह के बिजली बिल एवं भुगतान, उपभोक्ता शिकायत, बिजली बंद होने/बिजली बिल से संबंधित शिकायत



दर्ज करना, पूर्व में दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा। नया विद्युत कनेक्शन से संबंधित ऑनलाइन सुविधाएँ- नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना, आवेदन कनेक्शन की स्थिति जानना, आवेदन कनेक्शन हेतु भुगतान। विद्यमान विद्युत कनेक्शन व अन्य ऑनलाइन सुविधाएँ- भार परिवर्तन के लिए आवेदन, टैरिफ परिवर्तन के लिए आवेदन, नाम परिवर्तन के लिए आवेदन, मासिक खपत निकालने हेतु 'खपत कैलकुलेटर', खपत के आधार पर अनुमानित बिल, निकटतम भुगतान, केंद्र टैरिफ संबंधित जानकारी।

## मोबाइल शॉर्ट कोड एवं लॉन्ग कोड सेवा

मोबाइल शॉर्ट कोड सेवा के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता अपने मोबाइल से निर्धारित कोड टाइप कर उसे 166 या 51969 पर एस.एम.एस. करके जानकारी एस.एम.एस. द्वारा प्राप्त कर सकता है। मोबाइल लॉन्ग कोड सेवा के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता अपने मोबाइल से निर्धारित कोड टाइप कर उसे 9223166166 पर एस.एम.एस. करके जानकारी एस.एम.एस. द्वारा प्राप्त कर सकता है। एस.एम.एस. की दर उपभोक्ता के टैरिफ प्लान अनुसार होगी। एस.एम.एस. द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी का विवरण निर्धारित कोड जिसे उपभोक्ता को 166 या 51969 या 9223166166 पर एस.एम.एस. करना है।



## स्पॉट बिलिंग सेवा

छत्तीसगढ़ के 573 कार्यालयों के अंतर्गत लगभग 49 लाख उपभोक्ताओं को उनके द्वार पर ही स्पॉट बिलिंग सिस्टम के माध्यम से विद्युत देयक प्रदान किये जा रहे हैं। इन विद्युत देयकों में भुगतान हेतु कोड प्रदर्शित रहता है। फलस्वरूप उपभोक्ता उनका तत्काल भुगतान ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कर सकता है। बिल जारी करने हेतु 4811 मीटर वाचकों को रोजगार प्रदान किया गया है।

## शिकायत पर फीडबैक मिस कॉल सेवा (999712869)

उपभोक्ता की तकनीकी शिकायत (सप्लाई संबंधित शिकायत) सिस्टम में क्लोज कर दी गई हो, परन्तु उपभोक्ता की शिकायत नहीं सुलझी हो तो वह 999712869 नंबर पर मिस कॉल कर शिकायत के फाल्स क्लोजर की शिकायत कर सकता है।

## नए बिजली कनेक्शन मिस्ड कॉल सेवा (7404040625)

बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई मिस्ड कॉल सेवा शुरू की गई है, जिसमें उपभोक्ता 7404040625 पर मिस्ड कॉल देकर नए बिजली कनेक्शन के लिए अनुरोध करते हैं। उसके बाद सीएसपीडीसीएल कॉल सेंटर के कर्मचारी, उपभोक्ता की ओर से ऑनलाइन नए बिजली कनेक्शन फॉर्म भरने के लिए उपभोक्ता से संपर्क किया जाता है।





इस पहल के लिए अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह द्वारा एमडी श्री भीम सिंह तथा ईडी श्री वी. के. साय का अभिनंदन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किये गये सुशासन के आव्हान से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार करते हुए **'बिजली मितान बॉट'** की सुविधा उपभोक्ताओं के लिए प्रारम्भ की गई है। उपभोक्ता को अपनी बकाया राशि, अंतिम बिल और अंतिम भुगतान की जानकारी जाननी हो तो भी 'बिजली मितान बॉट' के माध्यम से जान सकते हैं। कुछ उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त न होने की शिकायत रहती है वे भी अब बड़ी आसानी से इस बॉट के माध्यम से बिल की पीडीएफ प्रति यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकरी भी प्राप्त की जा सकती है। बॉट में बिजली बिल भुगतान, मोबाइल नंबर पंजीकरण, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन, लोड परिवर्तन, नाम परिवर्तन, टैरिफ की जानकारी, बिजली चोरी की सूचना देने की सुविधा, स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारी के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की उपभोक्ता सेवाएं इस बॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम पॉवर कंपनी के व्हाट्सऐप बॉट नंबर 9425551912 को अपने (Contact) लिस्ट में सेव करें। सेव करने के बाद ऊपर दिए गए नंबर पर Hi लिखकर भेजे। इसके बाद आपको भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) का चयन करना होगा। भाषा चयन के बाद आपके द्वारा जिस नंबर से चैट किया जा रहा है, उस नंबर से पंजीकृत उपभोक्ता क्रमांक प्रदर्शित होने लगेगा, जिस उपभोक्ता क्रमांक की जानकारी आपको लेनी है उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको बॉट में उपलब्ध उपभोक्ता सेवाओं की लिस्ट प्रदर्शित होने लगेगी, इसके पश्चात आपके इनपुट के आधार पर बॉट उपभोक्ता सेवाओं की जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ता जिनका उपभोक्ता क्रमांक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत नहीं है वे अपने मोबाइल नंबर का पंजीकरण मोर बिजली ऐप, कंपनी की वेबसाइट (cspdcl.co.in), कॉल सेंटर 1912 एवं अपने बिजली ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं।


बिजली के साथ सबका विकास

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

बिजली मितान बॉट
वॉट्सएप / वेब

बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर खराबी, बिजली दुर्घटना,अपनी बकाया राशि, अंतिम बिल और अंतिम भुगतान की जानकारी, उपभोक्ता सेवाएं आदि की जानकारी, समस्या बताने और समाधान जानने की सुविधा

9425551912

# 400 के.वी. चालू लाइन में पहली बार टॉवर शिफ्टिंग साहस और प्रौद्योगिकी कौशल का अनूठा प्रयोग

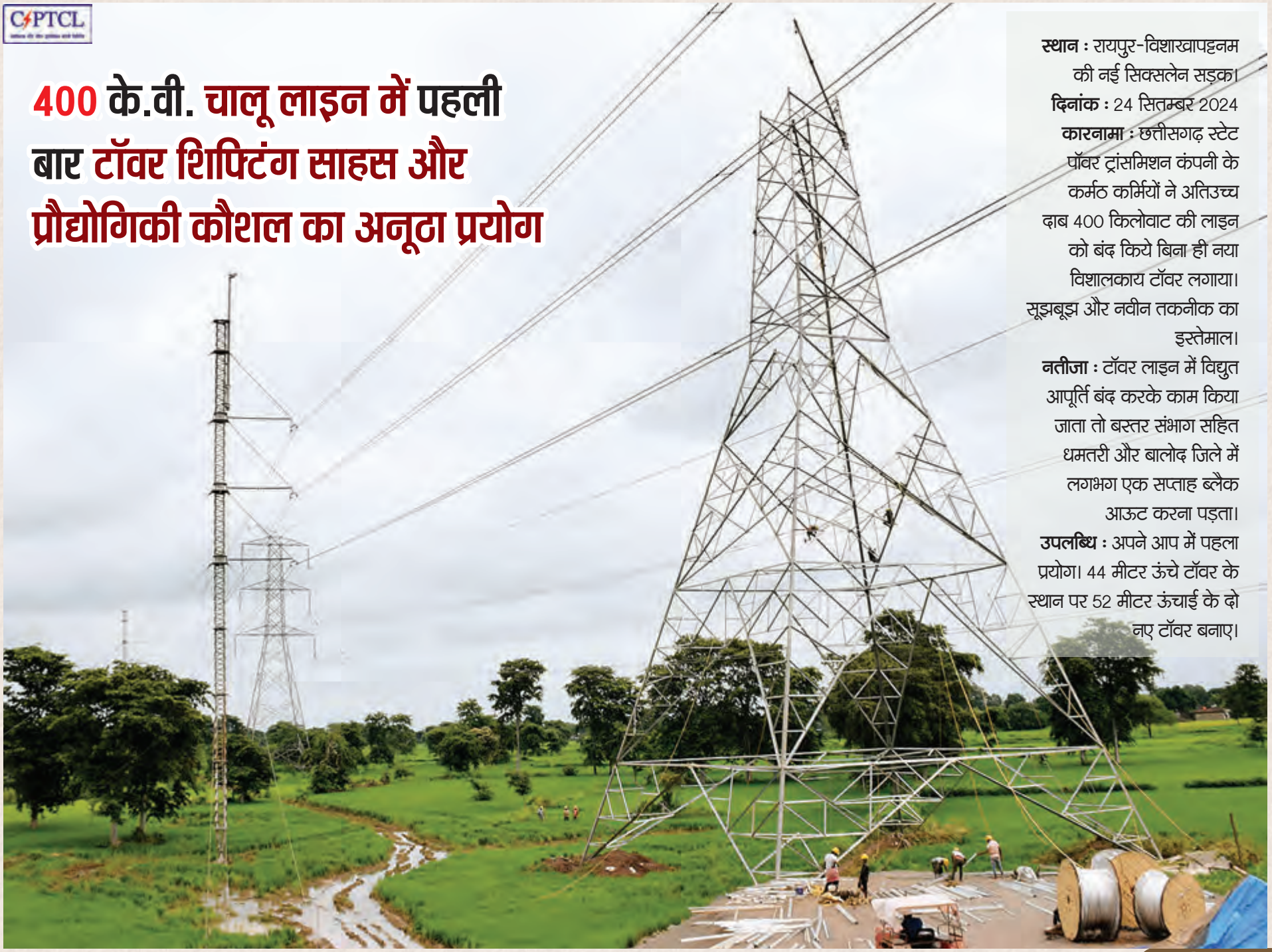

**स्थान :** रायपुर-विशाखापट्टनम की नई सिक्सलेन सड़क।

**दिनांक :** 24 सितम्बर 2024

**कारनामा :** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मठ कर्मियों ने अतिउच्च दाब 400 किलोवाट की लाइन को बंद किये बिना ही नया विशालकाय टॉवर लगाया। सूझबूझ और नवीन तकनीक का इस्तेमाल।

**नतीजा :** टॉवर लाइन में विद्युत आपूर्ति बंद करके काम किया जाता तो बस्तर संभाग सहित धमतरी और बालोद जिले में लगभग एक सप्ताह ब्लैक आऊट करना पड़ता।

**उपलब्धि :** अपने आप में पहला प्रयोग। 44 मीटर ऊंचे टॉवर के स्थान पर 52 मीटर ऊंचाई के दो नए टॉवर बनाए।




# नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास


श्री विष्णु देव साय
मान. मुख्यमंत्री जी के करकमलों से
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के
संयुक्त मुख्यालय भवन का
शिलान्यास
C/PDCL

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास 3 सितम्बर 2025 नवा रायपुर, अटल नगर में हुआ।

**संयुक्त मुख्यालय भवन की विशेषताएं**

- नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में शामिल उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित भवन सेक्टर 24 में भूखंड क्रमांक ए-47, कुल क्षेत्रफल 10017.30 वर्ग मीटर में प्रस्तावित है। जिसकी दूरी कि सी.बी.डी. रेल्वे स्टेशन से 500 मीटर है।
- भवन में 2 बेसमेंट प्रस्तावित है।
- इस निर्माण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् उत्पादन कंपनी को अधिकृत किया गया है।
- कार्य की अनुमानित लागत रुपये 199 करोड़ रु. है।
- भवन की लागत को तीनो कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से वहन की जाएगी।
- एजेंसी द्वारा प्रमाणित पांच सितारा ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित।
- हरित ऊर्जा के लिए प्रथम चरण में 55 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण में शत-प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की जानी है।
- भवन के ग्लास युक्त बाह्य सतह पर सोलर प्रणाली का उपयोग।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पांच सितारा रेटिंग और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुरूप भवन।
- भवन प्रबंधन प्रणाली नियंत्रित विद्युत, एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी), जल आपूर्ति, अग्निशमन, अग्नि अलार्म, ऑडियो-विजुअल, सीसीटीवी निगरानी।
- दो बेसमेंट में 350 कारों की पार्किंग व्यवस्था (ऊपरी बेसमेंट (81) में मैकेनिकल स्टेक पार्किंग)
- विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रावधान।
- स्टेट पॉवर कंपनियों का संयुक्त मुख्यालय भवन संस्था एवं प्रदेश के गौरव के प्रतीक स्वरूप अत्याधुनिक और हरित भवन के मापदंडों के अनुरूप होगा।
- भवन को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (गृहा) के निर्धारित पांच सितारा मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
- संपूर्ण भवन एकीकृत प्रणाली से प्रबंधित होगा, जिसे भवन प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) नियंत्रित कहा जाता है। इसके तहत नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा और यह नियंत्रित विद्युत, एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) जल आपूर्ति, अग्निशमन, अग्नि अलार्म, ऑडियो विजुअल, सीसीटीवी निगरानी से लैस होगा।
- वास्तुविद सलाहकार मे. मांडवीवाता कुतुब एसोसिएट्स, मुंबई,
- निर्माण कार्य मे. श्रीजीक्रूपा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) तथा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) मे. डेविड एडमसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, की नियुक्ति की गई है।
- निर्माण कार्य हेतु आशय पत्र 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। कार्य हेतु 30 महीने की अवधि निर्धारित है जो कि फरवरी 2028 में पूर्ण होगी।



CHHATTISGARH STATE POWER COMPANIES HEAD OFFICE NAVA RAIPUR ATAL NAGAR




SITE PLAN — PROJECT DESIGNED BY MANDVIWALA QUTUB AND ASSOCIATES

# पुरोधा : मण्डल से कंपनी तक

## ऊर्जा मंत्री : छत्तीसगढ़

| क्र | मंत्री | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री धनेश पाटिला | नवंबर 2000 से दिसंबर 2003 |
| | श्री ताम्रध्वज साहू (राज्य मंत्री) | नवंबर 2000 से दिसंबर 2003 |
| 2 | डॉ. रमन सिंह | दिसंबर 2003 से दिसंबर 2018 |
| | श्री पूनम चंद्राकर (राज्य मंत्री) | दिसंबर 2003-2004 |
| 3 | श्री भूपेश बघेल | दिसंबर 2018 से जुलाई 2023 |
| 4 | श्री टी एस सिंहदेव | जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 |
| 5 | श्री विष्णुदेव साय | दिसंबर 2023 से निरंतर छत्तीसगढ़ |

## अध्यक्षगण : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

| क्र | अध्यक्षगण | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री एस.के. मिश्रा (आईएएस) | 15/11/2000-9/03/2001 |
| 2 | श्री गोपाल तिवारी | 09/03/2001-07/03/2003 |
| 3 | श्री बी.एस. बनाफर | 07/03/2003-15/12/2003 |
| 4 | श्री एस.के. मिश्रा (आईएएस) | 15/12/2003-03/02/2004 |
| 5 | श्री अजय सिंह (आईएएस) | 03/02/2004-18/09/2004 |
| 6 | श्री राजीव रंजन | 18/09/2004-15/12/2008 |
| 7 | श्री पी. जॉय उम्मेन (आईएएस) | 16/12/2008-1/1/2009 |

## अध्यक्षगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ (5)

| | | |
|---|---|---|
| 8 | श्री पी. जॉय उम्मेन (आईएएस) | 1/1/2009 - 01/02/2012 |
| 9 | श्री शिवराज सिंह (आईएएस) | 01/02/2012-17/12/2018 |
| 10 | श्री अंकित आनंद (आईएएस) | 18/12/2018-29/01/2019 |
| 11 | श्री शैलेन्द्र शुक्ला | 29/01/2019-17/03/2020 |
| 12 | श्री सुब्रत साहू (आईएएस) | 17/03/2020-08/12/2020 |

## अध्यक्षगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ (3)

| | | |
|---|---|---|
| 13 | श्री अंकित आनंद (आईएएस) | 02/5/2022 -04/01/2024 |
| 14 | श्री पी. दयानंद (आईएएस) | 05/01/2024-04/10/2024 |
| 15 | डॉ. रोहित यादव (आईएएस) | 04/10/2024 |
| 16 | श्री सुबोध सिंह (आईएएस)<br>अध्यक्ष (पारेषण कंपनी) | 10/01/2025 से कार्यरत |
| 17 | डॉ. रोहित यादव (आईएएस)<br>अध्यक्ष (उत्पादन एवं वितरण कंपनी) | 10/01/2025 से कार्यरत |

## प्रबंध निदेशकगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

| क्र | प्रबंध निदेशक | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री एस.पी. चतुर्वेदी | 01/01/2009-28/02/2011 |
| 2 | श्री वी. के. श्रीवास्तव | 01/03/2011-31/10/2011 |
| 3 | श्री जी.एस. कलसी (प्रभारी) | 01/11/2011-20/11/2011 |
| 4 | श्री जनार्दन कर | 21/11/2011-30/05/2014 |
| 5 | श्री विजय सिंह (प्रभारी) | 30/05/2014-08/09/2014 |
| 6 | श्री एस. बी. अग्रवाल | 08/09/2014-07/09/2017 |
| 7 | श्री ओ.सी. कपिला (प्रभारी) | 08/09/2017-03/05/2018 |
| 8 | श्री के.आर.सी. मूर्ति | 04/05/2018-04/12/2019 |
| 9 | श्री राजेश वर्मा | 05/12/2019-15/01/2020 |
| 10 | श्री एन.के. बिजौरा | 15/01/2020-30/11/2022 |
| 11 | श्री एस. के. कटियार | 01/12/2022 - कार्यरत |

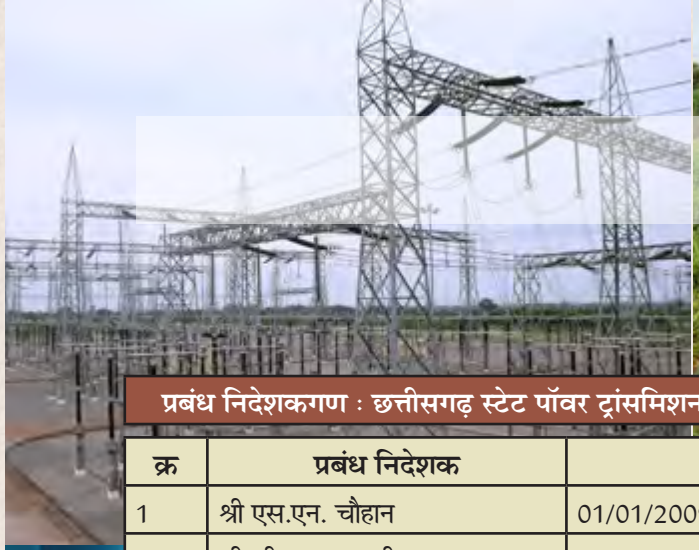





# पुरोधा : मण्डल से कंपनी तक

## प्रबंध निदेशकगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

| क्र | प्रबंध निदेशक | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री एस.एन. चौहान | 01/01/2009-30/09/2010 |
| 2 | श्री जी.एस. कलसी | 30/09/2010-28/02/2013 |
| 3 | श्री विजय सिंह | 28/02/2013-31/05/2017 |
| 4 | श्रीमती तृप्ति सिन्हा | 01/06/2017-04/12/2019 |
| 5 | श्री अशोक कुमार | 05/12/2019-28/06/2021 |
| 6 | श्री एस.डी. तेलंग | 28/06/2021-03/05/2022 |
| 7 | श्रीमती उज्ज्वला बघेल | 04/05/2022-04/12/2023 |
| 8 | श्री मनोज खरे (अति. प्रभार) | 05/12/2023-29/02/2024 |
| 9 | श्री आर. के. शुक्ला | 01/03/2024 - कार्यरत |





## प्रबंध निदेशकगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

| क्र | प्रबंध निदेशक | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री वी.के वर्मा | 01.01.2009 - 31.10.2009 |
| 2. | श्री विनोद श्रीवास्तव | 01.11.2009 - 30.09.2010 |
| 3. | श्री एस.एन चौहान | 01.10.2010 - 25.07.2011 |
| 4. | श्री जी.एस कलसी | 26.07.2011 - 03.11.2011 |
| 5. | श्री पी.एल विधानी | 03.11.2011 - 31.01.2012 |
| 6. | श्री डॉ. एस.पी शर्मा | 01.02.2012 - 31.07.2013 |
| 7. | श्री ए. के गर्ग | 01.08.2013 - 30.06.2017 |
| 8. | श्री अंकित आनंद (आईएएस) | 01.07.2017 - 05.02.2019 |
| 9. | श्री शैलेंद्र शुक्ला | 12.02.2019 - 17.03.2020 |
| 10. | श्री एम. क्यू अब्दुल हक (आईएएस) | 31.03.2020 - 04.08.2020 |
| 11. | श्री हर्ष गौतम | 18.08.2020 - 21.09.2020 |
| 12. | श्रीमती उज्ज्वला बघेल | 22.09.2020 - 06.07.2022 |

## प्रबंध निदेशकगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

| क्र | प्रबंध निदेशक | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री जी.एस. देशपांडे | 01/01/2009-30/09/2010 |
| 2 | श्री सुबोध कुमार सिंह (आईएएस) | 30/09/2010-03/03/2015 |
| 3 | श्री अंकित आनंद (आईएएस) | 03/03/2015-05/02/2019 |
| 4 | मोहम्मद क़ैसर अब्दुल हक़ (आईएएस) | 07/02/2019-03/08/2020 |
| 5 | श्री हर्ष गौतम | 17/08/2020-13/05/2022 |
| 6 | श्री मनोज खरे | 13/05/2022-31/03/2024 |
| 7 | श्री राजेश कुमार शुक्ला (अति. प्रभार) | 02/04/2024-01/07/2024 |
| 8 | श्री भीम सिंह कंवर | 11/07/2024 - कार्यरत |

## प्रबंध निदेशकगण : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

| क्र | प्रबंध निदेशक | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री वी.के. श्रीवास्तव | 01.01.2009 - 31.10.2011 |
| 2. | श्री जी.एस. कलसी | 31.10.2011 - 03.11.2011 |
| 3. | श्री एस.पी. शर्मा | 03.11.2011 - 31.07.2013 |
| 4. | श्री सुबोध कुमार सिंह | 31.07.2013 - 29.01.2019 |
| 5. | श्री गौरव द्विवेदी | 29.01.2019 - 27.04.2020 |
| 6. | श्री राजेश वर्मा | 30.04.2020 - 11.07.2022 |

# पुरोधा : मण्डल से कंपनी तक



## राज्य विद्युत मंडल, सदस्य (उत्पादन परियोजना)

| क्र | सदस्य (उत्पादन परियोजना) | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर के उपाध्याय | 28.06.2001 से 31.01.2002 |
| 2. | श्री एस बी एस चौहान | 01.02.2002 से 07.04.2002 |
| 3. | श्री बी एस बनाफर | 08.04.2002 से 20.04.2003 |
| 4. | श्री टी आर साकार | 21.04.2003 से 31.12.2003 |
| 5. | श्री बी आर एस बघेल | 29.02.2004 से 31.03.2007 |
| 6. | श्री एम बी मेडेकर | 10.12.2007 से 31.12.2008 |

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, सदस्य (उत्पादन)

| क्र | सदस्य (उत्पादन) | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर के उपाध्याय | 02.12.2000 से 27.06.2001 |
| 2. | श्री एस बी एस चौहान | 28.06.2001 से 26.06.2002 |
| 3. | श्री बी एस बनाफर | 27.06.2002 से 20.04.2003 |
| 4. | श्री ए के राय | 21.04.2003 से 31.05.2005 |
| 5. | श्री बी आर एस बघेल | 01.06.2005 से 03.01.2006 |
| 6. | श्री ए के द्विवेदी (अतिरिक्त प्रभार) | 02.02.2006 से 07.02.2006 |
| 7. | श्री एस पी चतुर्वेदी | 08.02.2006 से 31.12.2008 |

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, सदस्य (पारेषण एवं वितरण)

| क्र | सदस्य (पारेषण एवं वितरण) | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री गोपाल तिवारी | 02.12.2000 से 19.09.2001 |
| 2. | श्री शरद चन्द्र | 19.09.2001 से 17.03.2003 |
| 3. | श्री मनोरंजन कुमार | 12.03.2003 से 19.04.2003 |
| 4. | श्री के एस अरोरा | 19.04.2003 से 14.01.2004 |
| 5. | श्री ए के राय | 14.01.2004 से 01.02.2004 |
| 6. | श्री वाय एन जौहरी | 01.02.2004 से 20.09.2004 |
| 7. | श्री बी के शर्मा | 20.09.2004 से 31.01.2005 |
| 8. | श्री ए के द्विवेदी | 01.02.2005 से 30.04.2006 |
| 9. | एस पी चतुर्वेदी (अतिरिक्त प्रभार) | 02.05.2006 से 03.05.2006 |
| 10. | श्री मनोज डे | 03.05.2006 से 09.12.2007 |
| 11. | श्री वी के जैन | 09.12.2007 से 09.12.2008 |
| 12. | श्री वी के वर्मा | 09.12.2008 से 31.12.2008 |

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सचिव

| क्र | सचिव | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1 | श्री शरत चन्द्र | 30.12.2000 से 17.03.2002 |
| 2. | श्री ए एम के भरोस | 18.03.2002 से 31.03.2003 |
| 3. | श्री एस के सक्सेना | 01.04.2003 से 06.05.2003 |
| 4. | श्री ए एम के भरोस | 07.05.2003 से 29.02.2004 |
| 5. | श्री बी के शर्मा | 29.02.2004 से 10.11.2004 |
| 6. | श्री मनोज डे | 10.11.2004 से 04.05.2006 |
| 7. | श्री ए पी नामदेव | 04.05.2006 से 02.08.2006 |
| 8. | श्री वी के जैन | 02.08.2006 से 10.12.2007 |
| 9. | श्री वी के श्रीवास्तव | 22.12. 2007 से 31.12.2008 |

# बिजली से मुस्कान - बिजली से सम्मान - बिजली से स्वाभिमान - बिजली से उड़ान












## बिजली से 65 लाख उपभोक्ताओं को शक्ति


सी एस पी जी सी एल
CSPGCL
CSPTCL
CSPDCL


सी एस पी जी सी एल
CSPGCL
CSPTCL
CSPDCL